



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304 ]  
No. 304]नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2002/आषाढ़ 14, 1924  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2002/ASADHA 14, 1924

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2002

**विषय :—**सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान और निर्धारण) नियमावली, 1997 (जिसे इसमें इसके बाद एसजीडी नियमावली कहा गया है) के नियम-5 के अंतर्गत भारत में एपिक्लोरोहाइड्रिन के आयात के बारे में रक्षोपाय शुल्क की जांच पड़ताल।

**सा.का.नि. 471(अ).**—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, और इसकी सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान और निर्धारण) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए।

## (क) प्रक्रिया

भारत में एपिक्लोरोहाइड्रिन के आयात के संबंध में रक्षोपाय शुल्क की जांच पड़ताल शुरू करने का नोटिस 14-03-2002 को जारी किया गया था और भारत के असाधारण राजपत्र में 21-3-2000 को प्रकाशित किया गया था। आवेदन और एक प्रश्नावली नोटिस की एक प्रतिलिपि सहित सभी ज्ञात हितवद्ध पक्षकारों को 26-4-2002 तक अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई थी, अर्थात् :—

## घरेलू उत्पादक

- (i) तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. (टीपीएल), चेन्नई

## आयातक/प्रयोक्ता उद्योग

- (i) डा. येक एण्ड कं. (इंडिया) लि., पुणे
- (ii) अतुल लिमिटेड, बलसाड, गुजरात
- (iii) सिंथेटिक्स एंड पोलिमेर इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद
- (iv) पारिख रेसिन्स लि. (रेजिनोबा केमी. लि.), कानपुर
- (v) रेजिन्स एण्ड प्लास्टिक्स लि., रायगढ़
- (vi) पेट्रो एलडाइट प्रा. लि., चेन्नई
- (vii) पारिख रेसिन्स एंड पोलिमेर लि., उन्नाव, उ. प्र.
- (viii) भारत जनरल टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, कलकत्ता
- (ix) बंगाल पॉली रेसिन्स प्रा. लि., कलकत्ता

- (x) डेल्टा इंडस्ट्रियल रेसिन्स प्रा० लि०, मुम्बई
- (xi) प्रगति केमिकल्स लि०, मुम्बई
- (xii) केमवेल प्रा० लि०, बैंगलूर
- (xiii) आईपीसीए लेबोरेट्रिज लि०, मुम्बई
- (xiv) ईजी टर्म इंटरप्राइजेस, मुम्बई
- (xv) रतनचंद एंड को मुम्बई
- (xvi) सी०जे० शाह एंड कम्पनी, मुम्बई
- (xvii) मनाली केमिकल्स, मुम्बई
- (xviii) उर्मी केमिकल्स, मुम्बई
- (xix) रसिकलाल एंड कं०, मुम्बई
- (xx) अल्फा केमिकल कॉरपोरेशन, मुम्बई
- (xxi) परेश केमिकल्स कॉरपोरेशन, मुम्बई
- (xxii) रश्मि ट्रेडिंग कम्पनी, मुम्बई
- (xxiii) बी०के० इंटरप्राइजेज, बड़ौदा/मुम्बई

#### निर्यातक

- (i) दाइसो कं० लि०, जापान
- (ii) डौ केमिकल कम्पनी, यूएसए
- (iii) सोलवे एस०ए०, बेल्जियम
- (iv) हनवा केमिकल कॉरपोरेशन, कोरिया

#### एसोसिएशन

- (i) केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चेन्नै
- (ii) इंडियन रेजिन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई

2. आवेदन और प्रश्नावली सहित जांच प्रारंभ करने के नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों अर्थात् बेल्जियम, चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया आर०पी०, यू०के०, अमरीका सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके उच्चायोगों/दूतावासों के जरिए और यूरोपीय संघ, भारत में यूरोपीय आयोग का प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली को भी भेजी गई थी ।

3. डौ केमिकल कम्पनी, अमरीका और सोलवे एसए, बेल्जियम द्वारा अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय वृद्धि का अनुरोध किया गया था । निवेदित समय वृद्धि को स्वीकार कर लिया गया था और संबंधित पक्षकारों को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ।

4. दिनांक 14.3.2002 के नोटिस और प्रश्नावली के उत्तर निम्नलिखित पक्षकारों से प्राप्त हुए थे ।

**घरेलू उत्पादक**

तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० (टीपीएल), चेन्नई

**आयातक/उपयोक्ता उद्योग**

- (i) अतुल लि०, वालसाद, गुजरात\*
  - (ii) सिंथेटिक्स एंड पोलिमीर इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद\*
  - (iii) पारिख रेसिन्स लि० (रेसिनेवा केमी लि०) कानपुर
  - (iv) भारत जनरल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कलकत्ता\*
  - (v) पेट्रो एरालडाईट प्रा० लि०, चेन्नई\*
  - (vi) बंगाल पोली रेसिन्स प्रा० लि०, कलकत्ता\*
  - (vii) डेल्टा इंडस्ट्रीज रेसिन प्रा० लि०, मुम्बई\*
  - (viii) प्रगति केमिकल्स लि०, मुम्बई\*
  - (ix) केमवेल प्रा० लि०, बंगलूर\*
  - (x) बीके इंटरप्राइजेज, बड़ौदा
- \* काउंसल के माध्यम से

**निर्यातक**

- (i) दाइसों कं० लि०, जापान
- (ii) डौ केमिकल कम्पनी, यूएसए
- (iii) सोलवे एसए, बेल्जियम
- (iv) हानवा कॅमिकल कारपोरेशन, कोरिया

**एसोसिएशन**

केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चेन्नई

5. जांच पड़ताल के लिए आवश्यक समझी गई सूचना की पुष्टि की गई थी और इस कार्य के लिए अधिकारियों के एक दल ने घरेलू उत्पादक के परिसरों को दौरा किया था। जांच पड़ताल का निष्कर्ष घरेलू उत्पादक को भेज दिया गया था और सत्यापन रिपोर्ट में एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी रखी गई थी।

6. दिनांक 31 मई, 2002 को सभी हितबद्ध पक्षकारों की सार्वजनिक सुनवाई की गई जिसकी सूचना 26.4.2002 को भेजी गई थी। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को 6.6.2002 तक उनके द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों के लिखित निवेदन दायर करने, 7.6.2002 को अन्य पक्षकारों द्वारा दायर किए गए उत्तर प्राप्त करने और दिनांक 14.6.2002 तक खंडन यदि कोई हों तो

उन्हें दायर करने का अनुरोध किया गया था । निम्नलिखित पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया:-

- (i) तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० (टीपीएल), चेन्नई
- (ii) अतुल लिमिटेड, वलसाड, गुजरात
- (iii) सिंथेटिक्स एंड पोलिमेर इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद
- (iv) पारिख रेसिन्स लि० (रेसिनोवा केमी लि०), कानपुर
- (v) पेट्रो एरालडाईट प्रा० लि० चेन्नई
- (vi) डेल्टा इंडस्ट्रिअल रेसिन प्रा० लि०, मुम्बई
- (vii) सोलवे, एसए, बेल्जियम
- (viii) हानवा केमिकल कारपोरेशन, कोरिया
- (ix) यूरोपीय कमीशन (यूरोपीय संघ), नई दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दूसरी सार्वजनिक सुनवाई के लिए इस आधार पर अनुरोध किया कि टीपीएल ने 31.5.2002 को हुई सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उनके प्रश्नों का प्रभावी उत्तर नहीं दिया जिसके कारण वह विभिन्न मुद्दों पर कारगर ढंग से कार्यवाही नहीं कर सके । इस संबंध में यह देखा गया है कि अपनाई गई प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्थात् घरेलू उत्पादकों के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए प्रश्नों का उसी समय उत्तर देना आदेशात्मक नहीं है । सार्वजनिक सुनवाई के समय स्पष्टीकरण मागने का अवसर प्रदान करने का प्रयोजन अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को समझने में उत्पन्न संदेहों को दूर करना है । टीपीएल ने यह उल्लेख किया था और यह सहमति व्यक्त की थी कि वह अन्य पक्षकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना लिखित निवेदन प्रस्तुत करने के समय उपलब्ध कराएंगे । तदनुसार, टीपीएल ने अपने निवेदनों में आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये हैं । उसके अतिरिक्त केवल उसी सूचना को ध्यान में रखा जाता है जिसे लिखित में दिया जाता है । इस प्रकार प्राप्त समस्त सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया था और उन हितबद्ध पक्षकारों को भी उसकी प्रतियां दी गई थी जो अपने खंडन प्रस्तुत करते समय इनका खंडन कर सकते थे । कुछ मुख्य मुद्दे जिनका हितबद्ध पक्षकारों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, टीपीएल की क्षमता, आयातों में वृद्धि असंभावित घटनाएं, टीपीएल की उतरोत्तर मूल्य ह्रास की नीति, समायोजन योजनाओं की व्यवहार्यता आदि से संबंधित थे । इन सभी मुद्दों पर जांच परिणामों में उचित रूप से कार्यवाही की गई है और इस मामले में किसी अन्य सार्वजनिक सुनवाई के लिए मुझे कोई औचित्य मालूम नहीं होता है ।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर (खंडन) की एक प्रति उपलब्ध कराने और उसके संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए भी 20 जून, 2002 को एक अन्य अनुरोध किया गया है । यह अनुरोध इस आधार पर विचार किए जाने योग्य नहीं है कि इसे समस्त प्रक्रिया 14.6.2002 के पूरी होने के पश्चात को प्रस्तुत किया गया है और प्रक्रिया के अनुसार पक्षकारों को लिखित निवेदन प्राप्त करने के बाद खंडन प्रस्तुत करने की छूट है । प्रक्रिया में खंडन प्रस्तुत करने के पश्चात और निवेदन प्रस्तुत करने की परिकल्पना नहीं है । यदि ऐसे अनुरोध की अनुमति दी जाती है तो यह एक

समाप्त न होने वाली प्रक्रिया बन जाएगी जिसके परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं होगा। इसलिए इस अनुरोध को सहमति नहीं दी जा सकती।

### घरेलू उद्योग

ईसीएच पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का आवेदन तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० (जिसे इसमें इसके पश्चात संक्षेपण के लिए टीपीएल कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। भारत में ईसीएच का केवल टीपीएल द्वारा उत्पादन किया जाता है और पूरा घरेलू उत्पादन उन्हीं का हिस्सा है। इसलिए आवेदन को ईसीएच उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग की ओर दायर किया हुआ समझा गया है।

### जांचाधीन उत्पाद

जांचाधीन उत्पाद एपिक्लोरोहाइड्रिन (ईसीएच) है। ईसीएच एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र  $\text{CH}_2\text{-CH-CH-CH}_2\text{Cl}$  है, जिसे सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष सं० 2910.30 और सुसंगत वस्तु विवरण के आधार पर भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के 29103000 के अंतर्गत किया गया है। सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और आईटीसी के अधीन एपिक्लोरोहाइड्रिन का वर्गीकरण सुविधा के प्रयोजनार्थ दिया गया है और इससे जांचाधीन उत्पाद को शामिल करने का कार्यक्षेत्र किसी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होता है। ईसीएच का उत्पादन क्लोरीन में प्रोपाइलिन का मिश्रण करके किया जाता है जो निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप है। ईसीएच का उत्पादन प्रोपाइलिन में क्लोरीन को वर्धित तापमान पर गैस रूप में सीधा मिलाकर अलाइल क्लोराइड प्राप्त करके किया जाता है। अलाइल क्लोराइड को क्लोरोहाइड्रिन के रूप में जलीय माध्यम में डाइक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। डाइक्लोराइड का आगे जलीय अपघटन घूने को साबुनीकरण एजेंट के रूप में प्रयोग करके क्वथन तापमान पर किया जाता है। जलीय अपघटन की प्रतिक्रिया स्ट्रिपिंग टावर में पूरी की जाती है जहाँ ईसीएच का दोहन किया जाता है। कच्ची ईसीएच को फ्रैक्शनेशन पद्धति द्वारा संशोधित किया जाता है। ईसीएच एक पेट्रोकेमिकल है जिसे एपोक्सी रोजिन्स, कीटनाशकों और कुछ फार्मैसी उत्पादों में मूल कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयातित ईसीएच और घरेलू तौर पर उत्पादित ईसीएच समान है।

### बंधनबद्धताएं और प्रयोज्य शुल्कदर

टैरिफ शीर्ष सं० 2910.30 के अन्तर्गत अपने वाले ईसीएच के लिए यथा मूल्य 40% का बंधन है जिसके आयात में मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ईसीएच पर 1994-95 में आयात शुल्क (मूल + अधिभार यदि कोई हो) की प्रयोज्य दर यथा मूल्यानुसार 65% थी जो धीरे-धीरे कम होकर 1995-96 में 42% , 1996-97 में 32% , 1997-98 में 25% हो गई और 1999-2000 तथा 2000-2001 में बढ़कर 27.5% हुई जो 2001-2002 में यथामूल्य 25% बहाली से पहले थी।

### आयातों में वृद्धि

ईसीएच का मुख्यतः बेल्जियम, जर्मनी, जापान, कोरिया (आर.पी.) और अमरीका से आयात होता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ईसीएच का आयात और घरेलू उत्पादन इस प्रकार थे:-

**तालिका-1**

वर्ष	घरेलू उत्पादन (एम.टी.)	आयात (एम.टी.)		घरेलू उत्पादन के % के रूप में आयात
		मात्रा एम.टी.	मूल्य (लाख रु.)	
1996-97	3595	761	411.55	21.17
1997-98	2349	1931	901.41	82.20
1998-99	951	2933	1497.80	308.41
1999-00	951	4614	2104.74	485.17
2000-2001	3620	4294	2550.28	118.61
2001-02(जन0)	2997	4971*	2171.91	165.87

\*सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा यथा सत्यापित

वर्ष 1996-97 के बीच की अवधि के दौरान ईसीएच का आयात 1996-97 में 761 एमटी से बढ़कर 2000-01 में सर्वाधिक 4294 एमटी हो गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान जिसके आंकड़े जनवरी 2002 तक आयात पत्तनों पर सीमाशुल्क आयुक्त से सत्यापित किए गए हैं, ईसीएच का आयात 4971 एमटी था। वर्ष 2001-02 के वर्तमान वर्ष के दौरान ईसीएच का यथानुपात आयात 5965 एमटी पारिकलित होता है।

अन्तिम के साथ अन्तिम छोर की तुलना करने पर यह मालूम होता है कि ईसीएच का आयात 1996-97 में 761 एमटी से 6 गुना बढ़कर 2001-2002 (जनवरी तक) 4971 एमटी हो गया है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ईसीएच का आयात 1999-2000 में सर्वाधिक 4614 एमटी था जो 2000-01 में कम होकर 4294 एमटी हुआ और 2001-2002 (जनवरी तक) पुनः बढ़कर 4971 एमटी हो गया था। आयात में वर्षवार वृद्धि 1996-97 की तुलना में 1997-98 में 154% , 1997-98 की तुलना में 1998-99 में 52% , 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में 57% , 1999-00 की तुलना में 2000-01 में 7 % की कमी और 2000-01 की तुलना में 2001-2002 में पुनः (यथानुपात आधार पर) 40 % की वृद्धि हुई। अतः वर्षों से ईसीएच के आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसमें वर्ष 2000-2001 शामिल नहीं है जब उससे पहले वर्ष की तुलना में आयात 7 % कम हो गया था। तथापि, पिछले तीन वर्ष अर्थात् 1999-2002 के दौरान ईसीएच आयात प्रतिवर्ष औसतन 4958 एमटी था जो पहले के तीन वर्ष अर्थात् 1996-99 के दौरान 1875 एमटी के औसत आयात से 164 % अधिक है।

जहाँ तक घरेलू उत्पादन की तुलना में ईसीएच के आयात में वृद्धि का संबंध है। यह देखा गया है कि 1996-97 में ईसीएच का घरेलू उत्पादन 3596 एमटी था जो 2000-2001 में मामूली

बढ़कर 3602 एमटी और 2001-2002 (जनवरी तक) 2997 एमटी अर्थात् आनुपातिक आधार पर (पूरे वर्ष के लिए) 2001-2002 में 3596 एमटी हो गया था।

वर्ष 1996-97 में घरेलू उत्पादन की तुलना में ईसीएच के आयात का प्रतिशत 21.17 % था जो 1999-2000 में शीघ्रता से बढ़कर 485.17 % हो गया और तत्पश्चात् 2000-2001 में कम हो कर 118.61% हो गया परन्तु 2001-2002 में लगभग 47 प्रतिशत प्वाइंट बढ़कर 165.87 % हो गया था। वर्ष 1996-97 के प्रारंभिक आंकड़ों की तुलना में 2001-2002 में घरेलू उत्पादन में 165.87% की पर्याप्त वृद्धि मालूम होती है जो 1996-97 से लगभग आठ गुणा है। वर्ष 1997-98 की तुलना में भी जब आयात घरेलू उत्पादन का 82.2% था, 2001-2002 में आयात का प्रतिशत घरेलू उत्पादन की तुलना में दो गुणा हो गया था। इस प्रकार आयात में असीमित रूप से और घरेलू उत्पादन के अनुपात में अर्थात् दोनों प्रकार से वृद्धि हुई है।

कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि रक्षोपाय आपातकालीन उपाय होने के कारण आयात में कम अवधि में अचानक वृद्धि मालूम होनी चाहिए। इस मुद्दे के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया कि ईसीएच के आयात के संबंध में केवल पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान ईसीएच का आयात 1999-2000 में 4614 एमटी, 2000-01 में 4294 एमटी और 2001-02 (जनवरी तक) 3846 एमटी होने से कारण स्थिर रहा इसलिए ईसीएच के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई। तथापि, मुझे इस निवेदन में कोई समर्थन मालूम नहीं होता जो न तो तथ्यों और न ही कानून के आधार पर है। तथ्यों के आधार पर चालू वर्ष अर्थात् 2001-2002 (जनवरी तक) में आयात 2000-01 की तुलना में 40% बढ़ा है। जहाँ तक कानूनी प्रावधानों का संबंध है, इस तर्क का न तो घरेलू रक्षोपाय कानून और न ही रक्षोपाय संबंधी करार समर्थन करता है। व्यापार में भी डब्ल्यूटीओ के अधिकांश सदस्य पांच वर्ष अथवा अधिक अवधि के आयातों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस मामले से विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए जिनके संबंध में आगे विचार किया गया है मेरी धारणा है कि इस मामले में 1996-97 से आगे की अवधि के लिए आयातों के साथ-साथ अन्य मानदंडों पर विचार किया जाना पूर्णतः उचित होगा।

### **अप्रत्याशित घटनाएँ**

घरेलू उत्पादकों ने यह निवेदन किया गया है कि ईसीएच के उत्पादन के लिए इपाक्सी विनिर्माताओं के आयात प्रतिस्थापन के रूप में वर्ष 1992 में विचार किया गया था जिनकी स्थापित क्षमता लगभग 9000 एटी प्र0व0 थी और ईसीएच के आयात पर शुल्क की दर 115 % थी और इपाक्सी रेजिन्स के सामान्य प्रयोग के लिए 65 % तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए 20 % थी। जिस समय तक ईसीएच संयंत्र ने उत्पादन शुरू कर दिया था, सीमाशुल्क काफी कम हो गया था और आगे भी कम होता जा रहा था। उनके कुछ खरीदार एपाक्सी रेजिन्स के आयात के आघात को सहन नहीं कर सके और अन्ततः वर्ष 1998-99 में बंद हो गए। इसके अतिरिक्त निर्यातकों ने ईसीएच और एपाक्सी रेजिन्स दोनों के मूल्य कम कर दिए और बाजार पर अधिकार कर लिया जिसके कारण घरेलू उत्पादकों को अपना उत्पादन कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि वह अपने उत्पादों की बिक्री अपनी परिवर्ती लागत से बहुत कम कीमत पर भी नहीं कर सके।

कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बाजार में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई है जो रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने का औचित्य सिद्ध कर सके। उनके अनुसार अप्रत्याशित घटनाओं में सामान्यतः ऐसी घटनाएं शामिल होती हैं जिनका अनुमान डब्ल्यूटीओ के तत्वाधान में सदस्य देशों के वाताकारों द्वारा रियायत प्रदान करते समय अथवा उक्त जिम्मेदारी लेते समय नहीं लगाया गया था।

जहाँ तक अप्रत्याशित घटनाओं का संबंध है, यह मालूम होता है कि यूएस लैम्ब (16 मई, 2001 का पारित डब्ल्यूटी/डी.एस.177/ए.बी./आर, डब्ल्यूटी/डीएस 178/एबी/आर) में अपीलीय निकाय ने कहा था कि अप्रत्याशित घटना ऐसी परिस्थिति है जिसकी विद्यमानता अनुच्छेद xix के अनुसार लागू किए जाने वाले रक्षोपाय के लिए तथ्यात्मक मामले के रूप में अवश्य प्रदर्शित की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में यह देखा गया है कि यह एक तथ्यात्मक मामला है कि ईसीएच का उत्पादन शुरू होने और वास्तविक उत्पादन उपलब्ध होने की अवधि के बीच ईसीएच पर आयात शुल्क तुरंत कम कर दिए गए हैं जो 1996-97 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान ईसीएच के आयात मूल्य में हुई तुरंत कमी के समसामयिक है। इस अवधि के दौरान लागत, बीमा, भाड़ा (सीआईएफ) आयात कीमत 1528 अमरीकी डालर प्रति एमटी से कम होकर 1059 अमरीकी डालर प्रति एमटी हो गई थी। तथापि, इस संबंध में सर्वाधिक समीचीन तथ्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी सहायता उपलब्ध नहीं थी। घरेलू उत्पादकों ने ईसीएच का उत्पादन इस आधार पर शुरू किया था कि ईसीएच के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री प्रोपाइलिन उन्हें चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (CPCL) से उपलब्ध हो जाएगी लेकिन वह नहीं हुई क्योंकि उनके आपूर्तिकर्ता (CPCL) का उत्पादन उनके मौजूदा ग्राहकों के लिए ही पर्याप्त था। प्रोपाइलिन का वैकल्पिक घरेलू स्रोत भारतीय तेल निगम मथुरा से था जो बहुत दूर है और इसकी दुलाई खतरनाक होने के साथ-साथ इसकी लागत बहुत अधिक होती है। भारतीय तेल निगम ने साख सुविधा को मांग/आपूर्ति के अन्तर के कारण निलम्बित कर दिया है। ईसीएच का कारगर उत्पादन इस तरह से आयातित प्रोपाइलिन पर निर्भर रहा। पुनरपि चेन्नै पत्तन न्यास प्रोपाइलिन खतरनाक होने के कारण चेन्नै पत्तन पर इसके आयात की अनुमति नहीं देता है। इसलिए घरेलू उत्पादकों ने बाजारों के जरिए आयात की सुविधा हेतु चेन्नै से 200 कि.मी. दक्षिण कुड्डालोर में एक छोटे टर्मिनल की सुविधा का सृजन किया जो पूर्णतः दुर्बहनीय और महंगी है। घटिया अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त बिजली की अधिक लागत और वित्तपोषण के कारण ईसीएच का घरेलू उत्पादन आयातित ईसीएच की तुलना में और अप्रतिस्पर्धी हो गया। इन अप्रत्याशित घटनाओं के फलस्वरूप ईसीएच के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसका तथ्य यह भी है कि आयात शुल्क में कमी हुई और आयात की किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना अनुमति दी गई।

### गम्भीर क्षति

गम्भीर क्षति के निर्धारण के लिए किसी लक्ष्य से समी संबंधित घटकों और परिमाणनीय स्वरूप जिसका घरेलू उद्योग की स्थिति पर विशेष रूप से प्रभाव हो, संबंधित वस्तु के वास्तविक और साक्षेप रूप से आयात में वृद्धि की दर और मात्रा, आयात में वृद्धि द्वारा घरेलू बाजार का लिया गया हिस्सा,



बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और घाटों के स्तर में परिवर्तन और रोजगार के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

यद्यपि ईसीएच के आयात में वृद्धि की दर और मात्रा का वास्तविक और सापेक्ष रूप से आयात में वृद्धि शीर्ष के अन्तर्गत पहले ही विश्लेषण किया जा चुका है परन्तु अन्य पहलुओं पर आगे विचार किया गया है।

#### (क) घरेलू उत्पादन

घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पर लागू होने वाले विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने से यह मालूम होता है कि ईसीएच के एक मात्र घरेलू उत्पादक नामतः मैसर्स तमिलनाडु पैट्रोप्रोडक्ट्स लि० ने मार्च, 1995 के अन्तिम सप्ताह में उत्पादन शुरू किया और 1994-95 में मात्र 5 एमटी का उत्पादन किया। विचाराधीन अवधि के दौरान टीपीएल ने 1996-97 में ईसीएच का 3595 एमटी, 1997-98 में 2349 एमटी, 1998-99 और 1999-2000 में 951 एमटी तथा 2000-01 में 3620 एमटी उत्पादन किया। उन्होंने 2001-02 (जनवरी 2002 तक) ईसीएच का 2997 एमटी उत्पादन किया जो पूरे 2001-2002 के लिए यथा अनुपात रूप से 3596 एमटी परिकलित होता है। इस प्रकार घरेलू उत्पादन 1996-97 में सर्वाधिक 3595 एमटी से कम होकर 1998-99 और 1999-2000 में मात्र 951 एमटी रह गया। तत्पश्चात् ईसीएच का घरेलू उत्पादन 2000-2001 में 3620 एमटी और 2001-2002 में (यथानुपातिक) 3596 एमटी तक हुआ।

कुछ पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादकों ने 1998-99 में ईसीएच के आयात में वृद्धि के संबंध में रक्षोपाय जांच के लिए आवेदन किया था जबकि रक्षोपाय शुल्क लगाने के सभी आवश्यक मानदंड उस समय विविध प्रकार से याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिक थे जिन्हें महानिदेशक ने अस्वीकार कर दिया था। यदि याचिकाकर्ता का ईसीएच पर रक्षोपाय शुल्क लगाने का तब कोई मामला नहीं बनता था तो अब भी उनका कोई मामला नहीं बनता।

इस संबंध में यह देखा गया है कि टीपीएल ने वर्ष 1998-99 में आयातित ईसीएच पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए दिनांक 12.06.1998 को आवेदन किया था। यह तथ्यात्मक मामला है। तथापि, अधिक महत्वपूर्ण तथ्य उपर्युक्तानुसार यह है कि टीपीएल ने ईसीएच का उत्पादन मार्च, 1995 के अन्तिम सप्ताह में शुरू किया। इस प्रकार जब टीपीएल ने 12.06.98 को आवेदन किया तो उत्पादन शुरू होने के तुरंत बाद के वर्षों के लिए उनका ट्रेक रिकार्ड रहा और तीन वर्ष अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान ईसीएच के उत्पादन के आंकड़े क्रमशः 3134 एमटी, 3595 एमटी और 2349 एमटी थे और आयात के आंकड़े क्रमशः 2374 एमटी, 761 एमटी 1931 एमटी थे। इन आंकड़ों के विश्लेषण से ईसीएच के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति पहुँचाने वाले ईसीएच के बढ़े हुए आयात के लिए रक्षोपाय जांच शुरू करने हेतु प्रथम दृष्टया कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता और तदनुसार उस समय रक्षोपाय जांच शुरू करना उचित नहीं समझा गया था।

तथापि, घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त की गई आशंका के अनुसार ईसीएच का आयात बाद के वर्षों में बढ़ा। वर्ष 1998-99 में ईसीएच का आयात बढ़कर 2933 एमटी हो गया था जबकि 1997-

98 में इसकी मात्रा 1931 एमटी थी। आयात में और वृद्धि होकर इसकी मात्रा 1999-2000 में 4614 एमटी 2000-2001 में 4294 एमटी और 2001-2002 में (जनवरी तक) 4971 एमटी हो गई थी। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में ईसीएच का घरेलू उत्पादन मात्र 951 एमटी रह गया। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में घरेलू उत्पादन बढ़कर क्रमशः 3620 एमटी और (यथानुपातिक) 3596 एमटी हो गया। तथापि, अंतिम दो वर्ष में घरेलू उत्पादन में हुई इस वृद्धि को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है। टीपीएल ने अपने दिनांक 12.06.98 के आवेदन में आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एपाक्सी रेजिन्स के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना हेतु सीबी जेजी के साथ गठबंधन करने की परिकल्पना की थी जिससे उनके द्वारा उत्पादित ईसीएच की इस नई कम्पनी को आपूर्ति करने का क्षेत्र प्राप्त हुआ। तदनुसार, पैट्रो अरालडाइर प्रा० लि० नामक एक कम्पनी की स्थापना की गई जो 1999 में चालू हुई पीएपीएल एपाक्सी रेजिन्स का व्यवसाय कर रहे हैं और देश में ईसीएच के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं जो ईसीएच की आवश्यकता को केवल टीपीएल से पूरा कर रहे हैं जो टीपीएल द्वारा वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में ईसीएच के घरेलू उत्पादन में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। परन्तु इस घटना के संबंध में टीपीएल अधिक उत्पादन करने का कारण मालूम नहीं कर सका। यह कहना भी समीचीन होगा कि घरेलू उत्पादन की खपत 1996-97 से 2001-2002 (जनवरी तक) स्पष्ट रूप से बढ़कर 2546 एमटी से 6797 एमटी हो गई जो 206 % है परन्तु ईसीएच का घरेलू उत्पादन लगभग 3600 एमटी प्रतिवर्ष पर स्थिर रहा है जिसका उत्पादन स्तर 1996-97 में भी यही था।

#### (ख) क्षमता उपयोग

टीपीएल ने ईसीएच की अपनी स्थापित क्षमता 10,000 एमटी प्रतिवर्ष बताई है। तदनुसार, उन्होंने 1996-97 में 35.95% क्षमता का उपयोग किया जो 1997-98 में कम होकर 23.49% और 1998-99 तथा 1999-2000 में भी 9.51% रह गया। उपर किए गए उल्लेख के अनुसार वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में बढ़े हुए उत्पादन के अनुरूप क्षमता उपयोग में भी 1998-99 की तुलना में वर्ष 2000-01 और 2001-2002 (यथानुपातिक) के लिए क्रमशः 36.2% और 35.96% का सुधार दर्शाया गया है। तथापि, विचाराधीन अवधि के दौरान क्षमता उपयोग लगभग 36% से कम स्तर पर रहा।

#### (ख) बिक्री

टीपीएल ने पीएपीएल को ईसीएच की बिक्री को आबद्ध खपत के रूप में माना है परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीएपीएल एक अलग संयुक्त उद्यम सत्ता है जो घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात के लिए भी एपाक्सी रेजिन्स के उत्पादन का व्यवसाय करता है इसलिए टीपीएल द्वारा पीएपीएल को ईसीएच की बिक्री की आबद्ध खपत समझना उचित नहीं है। बहरहाल, चाहे इसका प्रयोग आबद्ध रूप से किया गया हो अथवा इसे बाजार में बेचा गया हो, इससे रक्षोपाय जांच के प्रयोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तथापि, पीएपीएल द्वारा एपाक्सी रेजिन्स के निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त ईसीएच को टीपीएल द्वारा डीईईसी स्कीम के अन्तर्गत माने गए निर्यात के आधार पर बेचा गया था। ईसीएच की इस बिक्री को घरेलू बिक्री का हिस्सा नहीं समझा जा रहा है।

टीपीएल ने 1996-97 में कुल 3753 एमटी ईसीएच की बिक्री की जिसमें से 1785 एमटी घरेलू बाजार में बेच गया और शेष 1968 एमटी का निर्यात किया गया था। वर्ष 1997-98 में घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों घटकर क्रमशः 1389 एमटी और 19 एमटी हो गए। वर्ष 1998-99 में घरेलू बिक्री और कम होकर 1241 एमटी रह गई तथा निर्यात में 118 एमटी का मामूली सुधार हुआ। वर्ष 1999-2000 में पीएपीएल को माने गए निर्यात के आधार पर घरेलू बाजार में की गई निर्यात बिक्री सहित घरेलू बिक्री की मात्रा 1656 एमटी थी जिसमें से पीएपीएल को 1196 एमटी घरेलू खपत के लिए, 360 एमटी माने गए निर्यात के आधार पर निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए और 100 एमटी को अन्य क्रेताओं को बेचा गया था। वर्ष 2000-2001 में टीपीएल द्वारा कुल 3221 एमटी की बिक्री गई थी जिसमें 401.57 एमटी ईसीएच का निर्यात, 626 एमटी की पीएपीएल को छोड़कर घरेलू बाजार में क्रेताओं को बिक्री और माने गए निर्यात के आधार पर निर्यात उत्पादन के लिए 1080 एमटी सहित शेष की पीएपीएल को की गई बिक्री शामिल है। वर्ष 2001-2002 में ईसीएच की कुल 3326 एमटी की बिक्री हुई थी जिसमें 516 एमटी पीएपीएल के अतिरिक्त घरेलू क्रेताओं को और शेष 2810 एमटी पीएपीएल को बेचा गया था जिसमें माने गए निर्यात के आधार 15,00 एमटी की मात्रा शामिल थी।

निम्न तालिका में घरेलू तौर पर उत्पादित ईसीएच के उत्पादन, बिक्री और अन्तिम भंडार के ब्यौरे दिए गए हैं।

**तालिका-2**

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	ईसीएच की बिक्री (एमटी)					अंतिम भंडार (एमटी)
		पीएपीएल	अन्य क्रेता	सकल घरेलू बिक्री	माने गए निर्यात सहित निर्यात	जोड़	
1996-97	3595	—	1785	1785	1968	3753	278
1997-98	2349	—	1389	1389	19	1408	1219
1998-99	951	—	1241	1241	118	1359	811
1999-00	951	1196	100	1296	360	1656	106
2000-01	3620	1113	626	1739	1482	3221	505
2001-02 (जनवरी तक)	2997	1310	516	1826	1500	3326	176

उपर्युक्त तालिकाबद्ध आंकड़ों से यह मालूम होता है कि घरेलू उत्पादकों ने 1996-97 में घरेलू बाजार में कुल 1785 एमटी ईसीएच की बिक्री की जो लगातार कम होकर 1997-98 में 1389 एमटी और 1998-99 में 1241 एमटी रह गई थी। उनकी घरेलू बिक्री में पीएपीएल द्वारा अपना उत्पादन शुरू करने और टीपीएल से ईसीएच को प्राप्त करना शुरू करने के बाद ही सुधार हुआ। पीएपीएल को बिक्री के फलस्वरूप घरेलू बिक्री में वृद्धि होकर वह 1999-2000 में 1296 एमटी 2000-2001 में 1739 एमटी और 2001-2002 (जनवरी तक) 1826 एमटी हो गई थी। यह मालूम

होता है कि घरेलू खपत में 1996-97 से 2001-02 (यथा आनुपातिक) तक स्पष्ट रूप से 167% की वृद्धि हुई। गतवर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष घरेलू खपत में वर्षवार वृद्धि 1997-98 में लगभग 30%, 1998-99 में 26%, 1999-2000 में 42%, 2000-01 में 2% और 2001-02 में 13% हुई थी। घरेलू बिक्री में भी तदनुसार वृद्धि होनी चाहिए जो वाद का विषय नहीं है। घरेलू बिक्री (माने गए निर्यात के आधार आपूर्त मात्रा को छोड़कर) 2001-02 में जनवरी तक 1826 एमटी थी अर्थात् आनुपातिक रूप से 1996-97 की तुलना में केवल 22% अधिक।

#### (घ) भंडार

घरेलू उत्पादकों का ईसीएच का अन्तिम भंडार 1996-97 में 278 एमटी, 1997-98 में 1219 एमटी, 1998-99 में 811 एमटी, 1999-2000 में 106 एमटी, 2000-01 में 505 एमटी और जनवरी, 2002 की समाप्ति पर 176 एमटी था। अंतिम भंडार में धीरे-धीरे कमी होकर यह 1997-98 में 1219 एमटी अधिकतम मात्रा से 2000-01 में बढ़कर 505 एमटी होने से पहले 1999-2000 में 106 एमटी रह गया और जनवरी, 2002 के अन्त में पुनः कम होकर 176 एमटी हो गया था।

#### (ङ.) रोजगार

घरेलू उत्पादकों ने यह निवेदन किया है कि गतपांच वर्षों में संयंत्र का किसी समय भी 36% संयंत्र क्षमता से अधिक प्रचालन नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई और लगभग 270 कार्मिकों 160 अधिकारियों और स्टाफ संवर्ग से लगभग 110 व्यक्तियों को रोजगार का नुकसान हुआ।

#### (च) उत्पादकता

टीपीएल की ईसीएच की उत्पादकता एमटी में प्रति कर्मचारी 1996-97 में 29.95 एमटी थी। यह कम होकर 1997-98 में 19.58 एमटी रह गई और 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान मात्र 7.93 एमटी थी। तथापि, उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादकता बढ़कर 2000-01 में 30.16 एमटी और 2001-02 में 32.21 एमटी हो गई थी। जहाँ प्रति इकाई नियोजित पूंजी का संबंध है, यह 1996-97 में 28.54 एमटी/करोड़ रुपए से कम होकर 1997-98 में 17.88, 1998-99 में 6.89 और 1999-2000 में 6.57 एमटी/करोड़ रुपए रह गई थी। इसमें वृद्धि होकर यह 2000-01 में 24.84 एमटी/करोड़ रुपए हुई परन्तु 2001-2002 में पुनः कम होकर 19.92 एमटी/करोड़ रुपए हो गई।

#### (छ) लाभकारिता

टीपी एलईसीएच की घाटे में बिक्री करता रहा है। उनकी बिक्री की वसूली उत्पादन लागत से कम है, अतः उन्हें घाटा हो रहा है। ईसीएच की उत्पादन लागत वर्षों से इस प्रकार रही:-

तालिका-3

वर्ष	उत्पादन की लागत (रु०मी.टन)	बिक्री प्राप्ति (रु०मी.टन)
1996-97	1,33,114	58426
1997-98	1,21,734	65531
1998-99	2,71,020	67341

1999-2000	3,38,615	66769
2000-01	1,39,906	75363
2001-02	1,11,673	65107

टी पी एल ने ई सी एच के अपने उत्पादन में घाटा उठाया है। वर्ष वार घाटा 1996-97 में 26.02 करोड़ रु०, 1997-98 में 18.52 करोड़ रु० 1998-99 में 16.65 करोड़ रु० 1999-00 में 21.02 करोड़ रु० 2000-01 में 26.08 करोड़ रु० और 2001-02 में 27.25 करोड़ रु० (अलेखा परीक्षित) का रहा था। जो घाटा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 1997-98 और 1998-99 में आरंभिक रूप से कम हुआ था उसमें वर्ष 1999-2000 से आगे बढ़ोत्तरी शुरू हो गई और चालू वर्ष में सर्वाधिक बढ़कर 27.25 करोड़ रु० का हो गया है। 2000-01 और 2001-02 में अधिक उत्पादन तथा अधिक बिक्रिया होने के बावजूद भी टी पी एल को इन वर्षों में अधिक घाटा हुआ है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जाता है कि टी पी एल को गंभीर क्षति हुई है जैसा कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में उनके निष्पादन में संमग्र रूप से अत्यधिक व्यवधान आया जब उनका उत्पादन लगतार दो वर्षों में घटकर 951 मि.टन हो गया और घरेलू बिक्रियां 1998-99 में 1241 मि.टन के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी और अगले वर्ष वे 1296 मि.टन पर बनी रही। इस अवधि के दौरान उनका क्षमता उपयोग भी घटकर 9.51% हो गया और ई सी एच के अपने प्रचालन में उन्हें इन वर्षों के दौरान लगभग 38 करोड़ रु० का भारी घाटा हुआ। आयातों के खतरे को भांपकर टी पी एल ने वर्ष 1998-99 में रक्षोपाय संरक्षण की मांग की थी और पी ए पी एल की स्थापना सहित अपने लिए विभिन्न उपायों को शामिल करते हुए एक समायोजन योजना तैयार की थी। इन उपायों से पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात् 2000-01 और 2001-02 में उनके निष्पादन में सुधार तो हुआ था किन्तु उन्हें कोई रक्षोपाय संरक्षण प्रदान नहीं किया था, ई सी एच के आयात निर्बाध रूप से जारी रहे जो भारत में 2000-01 में 4294 मि.टन और जनवरी 2002 तक 4971 मि.टन के हो गए थे। पी ए पी एल की स्थापना से टी पी एल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने संरक्षण, क्षमता उपयोग उत्पादकता और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि करने में समर्थ हुआ था किन्तु लगाई गई पूंजी, स्थिर घरेलू उत्पादन, क्षमता उपयोग के संबंध में उत्पादकता में कमी के रूप में उन्हें गंभीर क्षति का भारी खतरा बना रहा और बिक्रियां प्रत्यक्ष घरेलू खपत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई जिससे 2000-01 में 26.08 करोड़ रु० और 2001-02 में 27.25 करोड़ रु० (अलेखा परीक्षित) का घाटा हुआ अर्थात् वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में 37.87 करोड़ रु० के घाटे की तुलना में 2000-01 और 2001-02 में 53.38 करोड़ रु० का कुल घाटा हुआ था।

#### क्षति का कारण

निम्नलिखित तालिका से टी पी एल द्वारा ई सी एच की घरेलू बिक्रियों (माने गए निर्यात आधार पर निर्यात उत्पादन हेतु घरेलू बिक्रियों को छोड़कर) ई सी एच के आयातों तथा प्रत्यक्ष घरेलू खपत (घरेलू बिक्रियां जमा आयात) में घरेलू उत्पादन और आयातों के हिस्से का पता चलता है:

तालिका-4

वर्ष	घरेलू बिक्रियां (मी.टन)	आयात (मी.टन)	ए डी सी (मी.टन)	ए डी सी में घरेलू बिक्रियां	ए डी सी में आयातों का %
------	----------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------

				का % हिस्सा	हिस्सा
1996-97	1785	761	2546	70.1	29.9
1997-98	1389	1931	3320	41.8	58.2
1998-99	1241	2933	4174	29.7	70.3
1999-2000	1296	4614	5910	21.9	78.1
2000-01	1739	4294	6033	28.8	71.2
2001-02 (जनवरी तक)	1826	4971	6797	26.86	73.14

उपर्युक्त सारणी में दिए गए आंकड़ों से यह देखा जाता है कि 1996-97 में प्रत्यक्ष घरेलू खपत (ए डी सी) में टी पी एल का बाजार हिस्सा 70.01% था जो 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में घटकर क्रमशः 41.8%, 29.7% और 21.9% रह गया। घरेलू उत्पादकों द्वारा गवांए गए हिस्से को आयातों ने प्राप्त कर लिया जो 1996-79 में 29.9% से बढ़कर 1997-98 में 58.2%, 1998-99 में 70.3% और 1999-2000 में सर्वाधिक बढ़कर 78.1% हो गया। संयुक्त उद्यम कंपनी पी ए पी एल की स्थापना होने से ई सी एच के घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 2000-01 में मामूली बढ़कर 28.8% हो गया तथा 2001-02 में घटकर 26.66% हो गया जबकि इस अवधि के दौरान आयातित ई सी एच का हिस्सा मामूली रूप से घटकर क्रमशः 71.2% और पुनः बढ़कर 73.14% हो गया।

यह देखा जाता है कि ई सी एच के घरेलू उत्पादकों को उक्त क्षति मुख्यतः उनके द्वारा उठाए गए घाटे के रूप में हुई है ऐसा खासकर हाल ही की अवधि अर्थात् 2000-01 और 2001-02 के दौरान हुआ है इस संबंध में यह देखा जाता है कि 1996-97 से 2001-02 (जनवरी तक) तक की अवधि के दौरान ई सी एच का भारत में आयात नीचे तालिका में दी गई कीमतों पर किया गया था:

तालिका-5

वर्ष	सी आई एफ आयात कीमते अमरीकी डालर/मी.टन	सी आई एफ आयात कीमतें रु०/मी.टन में	पहुंच कीमत (सीआईएफ जमा आयात शुल्क)
1996-97	1528	54077	71382
1997-98	1235	46681	58352
1998-99	1242	51075	63844
1999-2000	1059	45621	58167
2000-01	1318	59483	75841
2001-02 (जनवरी तक)	1090	43691*	54057*

\* सीमा शुल्क आंकड़ों पर आधारित

टी पी एल ने यह बताया है कि वे पहुंच कीमत की समानता को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार में ई सी एच की बिक्री करते हैं और यह कि आयात कीमत में लगातार गिरावट आने के

कारण उन्हें अपनी बिक्री कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वित्तीय घाटा हुआ। वास्तविकता यह है कि टी पी एल द्वारा अपनी लागत से काफी कम कीमतों पर ई सी एच की बिक्री की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय घाटा हुआ है। भारत में ई सी एच का आयात किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना किया जाता है अतः आयातित ई सी एच की पहुंच कीमत द्वारा घरेलू बाजार में कीमत नियंत्रित होती है क्योंकि इससे क्रेताओं के लिए अपने खरीद संबंधी निर्णय लेने में तुलात्मक बेच मार्क उपलब्ध होता है।

वास्तविक तथ्य यह भी है कि ई सी एच की सी आई एफ आयात कीमत में लगातार गिरावट आई है। 1996-97 में सी आई एफ आयात कीमतें अमरीकी डालर/मी.टन में औसतन 1528 थी जो उसके बाद 2000-01 में 1318 अमरीकी डालर/मी.टन पर पहुंचने से पूर्व 1999-2000 में घटकर 1235, 1242 और 1059 हो गई और वे 2001-02 (जनवरी तक) में पुनः घटकर 1090 अमरीकी डालर/मी.टन हो गई। आयातों में वृद्धि का संबंध कीमत में आई इस गिरावट से है 1996-97 में आयात 761 मी.टन के हुए थे जो बढ़कर 1931 मी.टन 2933 मी.टन और 1999-2000 में 1059 अमरीकी डालर/मी.टन की न्यूनतम औसत सी आई एफ कीमत के साथ सर्वाधिक बढ़कर 4614 मी.टन पर पहुंच गए। 1998-99 और 1999-2000 तक घरेलू उत्पादन घटकर 951 मी.टन वार्षिक का रह गया। घरेलू उत्पादन का लगभग सफाया करके आयात कीमतें बढ़कर 1318 अमरीकी डालर/मी.टन हो गई किन्तु चूंकि 2000-2001 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 3620 मी.टन हो गया था जिसका मुख्य कारण पी ए पी एल खरीद संबंधी सहायता प्रदान करना रहा था इसलिए 2001-02 में आयात कीमतें पुनः घटकर 1090 अमरीकी डालर/मी.टन के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई इससे ई सी एच के घरेलू उत्पादन को खतरा उत्पन्न हो गया है।

कुछेक हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अमरीकी डालर में आयातित ई सी एच की सी आई एफ कीमत की टी पी एल के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि उनके उपभोक्ताओं ने उक्त सामग्री का भुगतान भारतीय रू० में किया है और इसलिए भारतीय रूपए में ही आयात कीमत की उपभोक्ता एवं टी पी एल दोनों के लिए प्रासंगिकता है। भारतीय रूपए में आयात कीमत में 1999-2000 में 45621 रू०/मी.टन की तुलना में 2001-02 में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। टी पी एल द्वारा विगत में न तो उचित मात्रा की बिक्री की जा रही थी और न ही उसकी बिक्री करने की मंशा थी उदाहरणार्थ 2000 में कीमतें उच्चतम स्तर पर थी। ऐसा मामला होने के कारण उनका अनुरोध है कि कीमतों में आई गिरावट टी पी एल के लिए प्रासंगिक नहीं है।

मुझे डर है कि यह तर्क पूर्णतः असंगत है। याचिकाकर्ताओं ने भारी निवेश करके ई सी एच के विनिर्माण के लिए 10,000 मी.टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ एक संयंत्र स्थापित किया है। उन्होंने इस संयंत्र की स्थापना निरर्थक ही नहीं की है। वस्तुतः किसी विनिर्माता से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति करने की किसी गंभीर मंशा के बिना संयंत्र की स्थापना करें। मामले की वास्तविकता यह है कि पी ए पी एल ने 1999 में किसी समय टी पी एल से सामग्री की खरीद शुरू की थी। इससे पूर्व टी पी एल द्वारा केवल अन्य घरेलू क्रेताओं को ई सी एच की आपूर्ति की जा रही थी किन्तु उनके लिए उनकी बिक्रियां वर्ष दर वर्ष घटती रही अर्थात् 1996-97 में 1785 मी.टन से घटकर 97-98 में 1389, 1998-99 में 1241 मी.टन से घटकर 1999-2000 में केवल 100 मी. टन साथ ही आयातित ई सी एच की पहुंच कीमतों में भी गिरावट

आई जो 1996-97 में 71382रु/मी.टन से घटकर 1999-2000 में 58167 रु/मी.टन हो गई 1997-98 और 1998-99 में दोनों वर्षों की समाप्ति पर उनका भंडार क्रमशः 1219 मी.टन और 811 मी.टन रहा था। इन तथ्यों के मद्देनजर इस बात का समुचित तर्क नहीं दिया जा सकता कि टी पी एल अपने क्रेताओं को सामग्री की आपूर्ति नहीं करना चाहता था। उनके पास क्रेताओं को अपनी सामग्री की बिक्री करने की सभी संभावनाओं को तलाश करने के पर्याप्त कारण थे।

कुछेक पार्टियों ने यह बताया है कि टी पी एल द्वारा विनिर्मित ई सी एच की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती थी और यह कि आयातित ई सी एच भिन्न भिन्न ग्रेडों के एपोक्सी रेजिनो के विनिर्माण हेतु बेहतर गुणवत्ता युक्त थी। इस संबंध में यह देखा जाता है कि टी पी एल आइ एस ओ 9002 मान्यता प्राप्त कंपनी है। उन्होंने दावा किया है कि उनका उत्पाद ई सी एच हेतु निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। याचिकाकर्ताओं द्वारा टी पी एल द्वारा विनिर्मित ई सी एच और आयातित ई सी एच की विशेषताओं की एक प्रति भी प्रस्तुत की गई थी जिससे यह पता चलता था कि उनका उत्पाद विभिन्न गुणवत्ता संबंधी मापदंडों के संबंध में आयातित ई सी एच के पूर्णतः अनुरूप है। टी पी एल पिछले छः वर्षों से ई सी एच का कारोबार कर रहा है और ग्राहकों को भेजने से पूर्व उनके द्वारा विनिर्मित ई सी एच की गुणवत्ता संबंधी कड़ी जांच की जाती है। नमूनों की जांच कच्ची सामग्री से लेकर तैयार उत्पाद के स्तर तक उत्पादन के प्रत्येक चरण पर की जाती है। उनके द्वारा टी पी एल, जो निर्यात प्रयोजनार्थ एपोक्सी रेजिनो का विनिर्माण करते हैं, को और भेषज उद्योग, जो गुणवत्ता के प्रति बेहद जागरूक होते हैं, को ई सी एच की आपूर्ति की जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि टी पी एल द्वारा उपलब्ध किए गए ई सी एच की गुणवत्ता संबंधित आयातों का कारण नहीं थी।

कुछेक हितबद्ध पार्टियों द्वारा जिन कारकों को उल्लेख किया गया है उनमें से एक कारक टी पी एल के निवेशकों द्वारा अपने तुलन पत्रों में इस बात का अभिकथन है कि उन्होंने ई सी एच की आपूर्तियां लाभकारी बाजारों तक सीमित कर दी है। मैं इस अभिकथन में ऐसा कुछ नहीं पाता हूँ जिससे इस दावे को समर्थन मिले कि टी पी एल ने अपने ग्राहकों को ई सी एच की आपूर्ति करने से मना कर दिया है। स्पष्टतः टी पी एल से उस स्थिति में ई सी एच का उत्पादन जारी रखने और उसे भारी घाटे पर बेचने की आशा नहीं की जा सकती है जब उनके पास भंडार पहले से ही बढ़ रहा हो और वे ई सी एच की उस छोटी सी मात्रा की बिक्री करने में भी समर्थ न हो जिसका वे उत्पादन करते हैं।

जैसा कि उपर देखा गया है कि घरेलू क्रेताओं द्वारा ईसी एच की अपनी जरूरतों को आयातों के जरिए पूरा करने का कारण आयातों की सस्ती कीमतों का होना प्रतीत होता है इस संदर्भ में यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि 2001-02 में ई सी एच के आयात 53935 रु/मी.टन की औसत सी आइ एफ कीमत पर पहली तिमाही में 1102 मी.टन से बढ़कर दूसरी तिमाही में 45098 रु/मी.टन की औसत सी आइ एफ कीमत पर 1232 मी.टन तथा तीसरी तिमाही में 38954 रु/मी.टन की औसत सी आइ एफ कीमत पर बढ़कर 1905.6 मी.टन हो गए। जनवरी 2002 में 38219रु/मी.टन की औसत सी आइ एफ कीमत पर 731.5 मी.टन ई सी एच का आयात किया गया था इस प्रकार यह देखा जाता है कि ई सी एच के आयातों की मात्रा में घटती हुई कीमतों के साथ वृद्धि होती रही है।



कुछेक पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 2000-01 में भारत में आयातित ई सी एच की पहुंच कीमत में उर्ध्वगामी रुख प्रदर्शित हुआ था जिससे टी पी एल को अपनी लागत वसूल करने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ। इस संबंध में मैं यह पाता हूँ कि आयातित ई सी एच की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रभाव ई सी एच के घरेलू उत्पादन पर भी पड़ना चाहिए और इसलिए आयातित ई सी एच की बढ़ी हुई सी आइ एफ कीमत का तात्पर्य अनिवार्यतः यह नहीं है कि उससे अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए टी पी एल को कोई अवसर उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः टी पी एल की समग्र उत्पादन लागत आयातित ई सी एच की पहुंच कीमत से काफी अधिक रही है और वे पहुंच कीमत की समानता को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार में ई सी एच की बिक्री करने की कोशिश करते रहे हैं। तथापि, आयातित सामग्री के पक्ष में ई सी एच की खरीद करने के निर्णय के पीछे एक महत्वपूर्ण पहलू आयातों से जुड़े 90-120 दिनों के बीच की लंबी ऋण अवधियों का होना रहा है। परिणामतः टी पी एल को भी अपनी नकदी की स्थिति को प्रभावित करते हुए अपने क्रेताओं को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया था। इस समस्या को आइ ओ सी मथुरा द्वारा प्रोपिलीन की आपूर्तियों पर ऋण शर्तों को स्थगित करके और गंभीर बना दिया गया था। दूसरा उल्लेखनीय पहलू यह है कि अधोगामी बाजार प्रणाली में घरेलू क्रेता यह आशा करते हैं कि कीमतें संभावित पहुंच कीमत की समानता के आधार पर निर्धारित की जाए ताकि आगे की बुकिंग को रोका जा सके इसके अलावा मौके पर कीमतें अधिकांशतः संविदा कीमतों से पर्याप्ततः कम होती हैं जिनका घरेलू कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कुछ पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति का कारण सस्ते आयात थे तो इसे अधिक समय तक उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि ई सी एच की आयात कीमतों में कच्ची सामग्रियों प्रोपिलीन और क्लोरिन की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण वृद्धि होने की संभावना है और यह सुझाव दिया गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने का निर्णय प्रचालित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर लिया जाए। इस संबंध में यह देखा जाता है कि ई सी एच की वर्तमान सी आइ एफ कीमतों को किसी निर्णय पर पहुंचने का आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि जांचोत्तर कीमत का जांचाधीन अवधि के दौरान चल रही कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आयात कीमतों में विभिन्न कारकों की वजह से वृद्धि हो सकती है जिनका उत्पादन की घरेलू लागत पर भी प्रभाव पड़ेगा। जांचोत्तर कीमतों पर जांच परिणामों को आधारित करना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय।

यह भी दावा किया गया है कि टी पी एल की परेशानी का कारण उसके द्वारा निर्यात बाजार का गवाया जाना है जिसमें कमी आई है और यह कि टी पी एल ने अपने निर्यात निष्पादन को सुधारने के प्रति और न कि देश में ई सी एच के आयातों के प्रति कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। आगे यह कहा गया है कि चूंकि टीपीएल द्वारा विगत में ईसीएच के उत्पादन की आपूर्ति भारतीय उपभोक्ताओं को करने के बजाय इतनी मात्रा में उसका निर्यात किया जा रहा है जितनी मात्रा में वह घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में यह देखा जाता है कि टी पी एल ने अपने आवेदन में इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अड़चनों के बावजूद उन्हें अपना क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए कम प्राप्ति पर ईसी एच का निर्यात करने और लागत कम करने के लिए बाध्य किया गया था। इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ईसीएच का उत्पादन घरेलू खपत और निर्यात बाजार, दोनों के लिए समान होता है। ऐसा घरेलू उद्योग जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं था, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की मुश्किल से ही आशा की जा सकती है। आयातों से हुई क्षति का प्रभाव टीपीएल के निर्यात निष्पादन पर भी पड़ा है। तथापि, टीपीएल ने

वर्ष 2001-02 में डीईईसी योजना के तहत माने गए निर्यात के आधार पर पीएपीएल को 1500 मी0 टन ईसीएच की आपूर्ति की जिसे माल द्वारा भारतीय तट को छोड़े बिना निर्यात माना जाता है।

निष्कर्षतः यह पाया जाता है कि ईसीएच के घरेलू उत्पादक को गंभीर क्षति हुई है और उसे ईसीएच के आयातों में वृद्धि होने से आगे और गंभीर क्षति होने का खतरा है।

### **सकारात्मक समायोजन**

बढ़े हुए आयातों द्वारा पेश की गई प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उत्पादक ने उसके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। आवेदकों ने 3 वर्ष की अवधि में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादन लागत कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव किया है, अर्थात् :

(क) अनेक पैटोलियम उत्पादों/अन्य रसायनों को हैंडल करने के लिए इन्नोर सेटेलाइट पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय आकार के एक टर्मिनल का निर्माण करना जिससे कुड्डालोर पर प्रोपिलीन का आयात करने के लिए उनके द्वारा व्यय की गई उच्च विलम्ब लागत और दूरस्थ स्थानों से घरेलू प्रोपिलीन को लाने पर आने वाली उच्च परिवहन लागत की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्हें इसके वर्ष 2004 तक पूरा हो जाने की आशा है। विलम्ब लागत और उच्च परिवहन लागत, जिसकी बचत की जा सकती है, का ईसीएच के बारे में अनुमान उन्होंने लगभग 3000-5000रु0/-मी0 टन लगाया है।

(ख) क्लोरीन, जो कि एपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्रियों में से एक प्रमुख कच्ची सामग्री है, की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्पिक की हैवी कैमिकल्स डिवीजन का अर्जन कर लिया है तथा आगे उनकी योजना क्लोरीन की लागत को कम करने की एक मात्र मंशा से हैवी कैमिकल्स डिवीजन के परिसर में कारखानागत विद्युत संयंत्र स्थापित करने की है जिससे ईसीएच यूनिट द्वारा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में मदद मिलेगी। क्लोरीन अन्तर्ण लागत, जो इस समय 4500रु0/मी0 टन है, कारखानागत विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने से उसे अगले तीन वर्ष की अवधि में घटाकर 1500रु0/मी0 टन किया जा सकता है।

(ग) कच्ची सामग्रियों में से एक कच्ची सामग्री चूना को कम लागत पर प्राप्त करना तथा उसकी शुद्धता को बढ़ाकर कम से कम 90 % करने के लिए चूना के घरेलू उत्पादकों के साथ आगे बातचीत करना जिससे प्रक्रिया संबंधी समस्या का समाधान होगा और लागत में कमी आएगी।

(घ) टीपीएल की संवर्धित मूल्य ह्रास नीति से यह सुनिश्चित होगा कि मूल्य ह्रास लागत को वर्ष 2004-05 तक बटटेखाते डाला जा सके जिससे वे अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। यह बताया गया है कि वर्ष 2001-02 के दौरान 111,673रु0/मी0 टन की समग्र उत्पादन लागत चार वर्ष की अवधि में (वर्ष 2005-06में) घटकर 50,423रु0/मी0 टन हो जाएगी।

(ङ.) कच्ची सामग्रियों की खपत को कम करने तथा स्ट्रीम क्षमता को बढ़ाने के लिए ईसीएच संयंत्र में अलाइल क्लोराइड उत्पादन हेतु नए मिक्सर की स्थापना करना।

कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने समायोजन संबंधी योजनाओं की व्यवहार्यता और ईसीएच की उत्पादन लागत में बचत की संभावित मात्रा के बारे में संदेह व्यक्त किया है। जहां तक टीपीएल के संवर्धित मूल्य ह्रास का संबंध है, यह बताया गया है कि किसी रसायन संयंत्र में रख-रखाव की लागत और वह भी पूर्ण रूप से मूल्य हासित संयंत्र में काफी अधिक होगी और ऐसी लागत कम मूल्य ह्रास के रूप में कमी के समायोजन से अधिक होगी। कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह बताया है कि टीपीएल द्वारा परिकल्पित समायोजन संबंधी योजनाओं में न तो संबद्ध निवेशों की मात्रा आंकी गई है और न ही

संभावित लाभ का अनुमान लगाया गया है। समायोजन योजना कथन मात्र है, जिसकी आवश्यक साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और न ही उसे संलग्न किया गया है। कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह दावा किया है कि चूंकि टीपीएल ने कारखानागत विद्युत संयंत्र शुरू कर दिया है और वह चालू हो चुका है इसलिए क्लोरीन की लागत कम हो जानी चाहिए और इसलिए यह भावी समायोजन योजना का भाग नहीं बन सकता। इसी प्रकार अलाइल मिक्सर संयंत्र के बारे में यह तर्क दिया गया है कि उसकी स्थापना की जा चुकी है और उसका लाभ मिलने आरंभ हो जाने चाहिए और इसलिए उसकी भी अनदेखी करने की जरूरत है।

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजनाओं की जांच की गई है। संवर्धित मूल्य ह्रास के कारण लागत में कमी संबंधी प्रयास यद्यपि यह सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हो सकता है और कंपनी इस प्रकार के लाभों की हकदार हो सकती है किन्तु चूंकि इसकी पूर्ति उत्पाद की कीमत के जरिए नहीं की जा सकती इसलिए उत्पादन लागत निकालने के प्रयोजनार्थ इसे शामिल न करने की जरूरत है और रक्षोपाय शुल्क की मात्रा की गणना करने के लिए मूल्य ह्रास की केवल सामान्य दर की ही अनुमति दी जा रही है।

विद्युत लागत कम करने के लिए टीपीएल द्वारा कारखानागत विद्युत उत्पादन सुविधा की स्थापना करने की दिशा में उपाय किए जा चुके हैं। यह सुविधा स्थापित की जा चुकी है और इसके जून, 2002 तक चालू हो जाने की आशा है जो अगले दो वर्षों की अवधि में स्थायी बन जाएगी। इससे आगे चलकर उन मांग आधारित अधिकतम प्रभाओं में धीरे-धीरे पर्याप्त कमी आएगी, जिनका टीपीएल द्वारा भुगतान तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को किया जा रहा है और परिणामतः क्लोरीन की लागत में पर्याप्त कमी आ सकती है। रक्षोपाय जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस जारी किए जाने के बाद मार्च 2002 में अलाइल क्लोराइड मिक्सर चालू किया गया है। उत्तम खपत मापदण्डों के लिए रिएक्टर को स्थायी करने हेतु टीपीएल द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं जो क्षमता उपयोग की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करेंगे। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे कुशलता और आनस्ट्रीम कारक को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने के लिए जारी रखा जाएगा। जहां तक इन्नोर में उक्त टर्मिनल का संबंध है, टीपीएल ने एक कंपनी वैन ओमेरन मैक टैंक टर्मिनल्स, जिसे वोपाक सिकाल टर्मिनल लि0 के नाम से जाना जाता है, को वोपाक (40%), सिकाल (5 %), टीपीएल (35 %), तथा टिडको (11%), की इक्विटी भागीदारी के साथ प्रवर्तित किया है। टीपीएल ने अनेक पैट्रो रसायन उत्पादों की हैंडलिंग के लिए 32 टैंकों की स्थापना का प्रस्ताव किया है और इस परियोजना हेतु उन्होंने लगभग 30 एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया है। उन्होंने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं। टीपीएल परियोजना की कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद ट्रैफिक आंकड़ों को देश में पहले निगमित पत्तन के समग्र ट्रैफिक आंकड़ों में विभक्त कर दिया गया है। पत्तन ने टीएनईबी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र हेतु कोयले की हैंडलिंग करते हुए जून, 2001 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। सिकाल टीपीएल की एक सहायक कंपनी है, जो कोयले की एकमात्र हैंडलिंग एजेंसी है। पत्तन के चरण- II में 4 वर्षों, 3 तरल कार्गो के लिए और एक कोयले के लिए, की स्थापना करने का विचार है। इन परियोजनाओं के लिए पत्तन प्राधिकारियों ने भारत सरकार से सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त कर ली है। पत्तन प्रबंधन ने इन्नोर में मेरीन लिक्विड टर्मिनल हेतु रुचि की अभिव्यक्ति मांगी है। टीपीएल ने इस बारे में अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं जिन्हें सितम्बर, 2002 के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इन्नोर पत्तन को यह कार्य 2004 तक शुरू हो जाने की आशा है। टिडको ने भी पत्तन के नजदीक एक पैट्रो रसायन पार्क का प्रस्ताव किया है तथा उसने लगभग 2500

एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया है और उनके संभावित भागीदारों द्वारा ठिडको से बातचीत की जा रही है। इस मोर्चे पर टीपीएल और ठिडको के बीच सहयोगात्मक प्रयास किए जाने की संभावना है। पुनर्निर्माण योजनाओं का विधिवत विश्लेषण करने के बाद और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह समझा जाता है कि गंभीर क्षति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा के प्रति सकारात्मक समायोजन करने के लिए घरेलू उत्पादक को तीन वर्ष की अवधि तक संरक्षण की जरूरत होगी।

### **सार्वजनिक हित**

कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से किसी सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं होगी। इसके विपरीत रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से सार्वजनिक हित पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अनेक अंतिम उपयोक्ता उद्योग बंद हो सकते हैं। इस संबंध में यह अभिमत व्यक्त किया जाता है कि 'सार्वजनिक हित' अभिव्यक्ति के दायरे में केवल उपभोक्ता हित ही नहीं आते हैं। यह काफी व्यापक पद है जिसके दायरे में व्यापक सामुदायिक हित को ध्यान में रखते हुए सामान्य सामाजिक कल्याण आता है। चूंकि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से क्रेताओं के हाथों में आयातित ईसीएच की लागत में वृद्धि हो सकती है, इसलिए इसका प्रभाव उससे विनिर्मित अंतिम उत्पादों पर भी पड़ सकता है, अतः रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। रक्षोपाय शुल्क लगाने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को सकारात्मक समायोजन हेतु समय प्रदान करना है ताकि वह बढ़े हुए आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति का मुकाबला कर सके। अतः उक्त अवधि के लिए और यथोचित सीमा तक रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से न केवल ग्राहकों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, कम होगा अपितु उन्हें अपनी जरूरतों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पूरा करने के लिए व्यापक विकल्प की अनुमति भी मिलेगी। जिन घरेलू उत्पादकों ने भारी सार्वजनिक निवेश से संयंत्रों की स्थापना की है, वे अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध करते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान करते हैं। अतः 'रक्षोपाय शुल्क', जिससे घरेलू उत्पादक बढ़े हुए आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना करने में समर्थ होंगे, ईसीएच के क्रेताओं और ईसीएच से विनिर्मित उत्पादों के क्रेताओं के दीर्घकालिक हित में भी होगा। अतः यह माना जाता है कि ईसीएच पर रक्षोपाय शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा।

कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि आवेदक ईसीएच का एकमात्र उत्पादक होने के कारण रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी और वह घरेलू बाजार का शोषण करेगा। यहां यह देखना उचित है कि घरेलू उत्पादक के पास निर्यातकों की पर्याप्ततः उच्च क्षमता की तुलना में कुल 10,000 टीपीए की कुल क्षमता है। भारत में ईसीएच के आयातों की अनुमति किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के बिना प्रदान की जाती है। अप्रतिबंधित आयातों के मद्देनजर यह अनुमान लगाना सही नहीं है कि टीपीएल ने, खासकर उस स्थिति में किसी एकाधिकार का लाभ उठाया/उठा रहा है जब वर्ष 1998-99 से 2001-02 (जनवरी तक) की अवधि के दौरान आयातों का हिस्सा प्रत्यक्ष घरेलू खपत का औसतन लगभग 70 % था। कानून में भी इस बात का उपबंध नहीं है कि किसी अकेले उत्पादक के हित की तब भी रक्षा नहीं की जानी चाहिए जब वह रक्षा किए जाने का समुचित रूप से पात्र हो। रक्षोपाय शुल्क लगाने का उद्देश्य एकाधिकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित करना नहीं है बल्कि घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है यदि बढ़े हुए आयातों से उन्हें गंभीर क्षति हुई है या क्षति का खतरा बना हुआ है ताकि उन्हें बढ़े हुए आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति के साथ सकारात्मक समायोजन करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

कुछ पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि टीपीएल ईसीएच की घरेलू मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है और इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से केवल पीएपीएल, जिसके लिए टीपीएल ईसीएच की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है, को लाभ पहुंचेगा। यह दावा किया गया है कि टीपीएल द्वारा सृजित क्षमता का आकलन सतत आधार पर वास्तविक उत्पादन के संबंध में कभी नहीं किया गया है और किए गए अधिकतम उत्पादन को ही टीपीएल की क्षमता के रूप में माना जा सकता है। इस संबंध में यह देखा जाता है कि घरेलू उत्पादक ने गोपनीय आधार पर अपनी क्षमता का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि यदि उन्हें उच्चतर लोड फैक्टर पर संयंत्र को चलाने का अवसर मिल जाए तो वे अल्पावधि में अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और मांग को पूरा कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस मामले की परिस्थितियों में, जिनमें घरेलू उत्पादक क्रेताओं को सामग्री की बिक्री करने में समर्थ नहीं था, केवल उत्पादित मात्रा को ही संयंत्र की क्षमता मानी जानी चाहिए। इसके प्रतिकूल उपलब्ध किए गए किसी साक्ष्य के अभाव में यह मानना कि उनके पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है अथवा यह मानने का कोई आधार नहीं है कि आयात इसलिए आवश्यक थे क्योंकि टीपीएल मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं था।

आगे यह देखा जाता है कि टीपीएल ने 10,000मी० टन वार्षिक की स्थापित क्षमता वाले एक संयंत्र की स्थापना की है। जैसाकि सत्यापन किया गया है, टीपीएल ने एक माह में 547 मी० टन का अधिकतम उत्पादन और एक दिन में 28.14 मी० टन का उत्पादन किया। तदनुसार, वे निसंदेह ईसीएच का 6500-8500 मी० टन वार्षिक का उत्पादन कर सकते हैं। इसकी तुलना में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 (जनवरी तक) के दौरान पीएपीएल की जरूरत सहित ईसीएच की प्रत्यक्ष घरेलू खपत 6000 से 8000 मी० टन वार्षिक तक की रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर मेरी राय यह है कि यह मानना उचित नहीं होगा कि टीपीएल ईसीएच की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

इस बात का उल्लेख करना भी संगत होगा कि सीबा इंडिया प्रा० लि० (सीआईपीएल) द्वारा वेंटिको फरफार्मैस पॉलिमर्स प्रा० लि० के पक्ष में पीएपीएल में अपनी हैसियत निहित करने के परिणामस्वरूप टीपीएल को बेचे जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रथम मनाही के अधिकार को छोड़ने, आपूर्ति संबंधी नए करार द्वारा अधिक्रमण करने के लिए पीएपीएल को ईसीएच की आपूर्ति हेतु मौजूदा आपूर्ति संबंधी करार को स्थगित करने तथा सीआईपीएल को विभिन्न करारों के तहत उसके दायित्वों और कर्तव्यों को मुक्त करने के लिए सहमत होना पड़ा था। संविदाओं के इस समय पूर्व समापन के प्रतिफल में और उक्त अधिकारों की सुपुर्दगी के लिए टीपीएल को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में सीआईपीएल द्वारा 630.248 हजार रु० की राशि तय की गई थी। इसके अलावा पीएपीएल ने ईसीएच के उपभोक्ता के रूप में और एपोक्सी रेजिनों का सबसे बड़ा विनिर्माता होने के नाते ईसीएच पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का विरोध किया है यद्यपि पीएपीएल पर टीपीएल और मै० वेंटिको इंटरनेशनल का संयुक्त स्वामित्व है। अतः यह मानने का कोई आधार नहीं है कि ईसीएच पर रक्षोपाय शुल्क की मांग करने में टीपीएल और पीएपीएल के हित समान रूप से प्रभावित होते हैं।

अतः यह माना जाता है कि ईसीएच पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना सार्वजनिक हित में है।

### अनंतिम रक्षोपाय शुल्क

चूंकि जांच पूरी होने के बाद अंतिम जांच परिणाम निकाले गए हैं, इसलिए वर्तमान मामले में किसी अनंतिम उपाय की सिफारिश करना जरूरी नहीं समझा जाता है।

### भारत को हुए निर्यात में देशों का हिस्सा

सत्यापित सूचना के अनुसार वर्ष 2001-02 (जनवरी तक) के दौरान भारत को हुए ईसीएच के निर्यात में देशों का हिस्सा निम्नानुसार रहा था:-

देश/क्षेत्र	मात्रा (मी० टन)	% हिस्सा
बेल्जियम	618	12.43
जर्मनी	1109	22.31
जापान	364	7.32
कोरिया गणराज्य	1515	30.48
यू.एस.ए.	1365	27.46
<b>कुल</b>	<b>4971</b>	<b>100</b>

### निष्कर्ष एवं सिफारिश

उपर्युक्त जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में हुए ईसीएच के संवर्धित आयातों से ईसीएच के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है तथा उन्हें आगे और गंभीर क्षति होने का खतरा है और ऐसा करना सार्वजनिक हित में होगा कि भारत में ईसीएच के आयातों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए।

रक्षोपाय शुल्क की उस राशि का आकलन करने के लिए, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए पर्याप्त होगा और जिससे सकारात्मक समायोजन सुविधाजनक बनेगा, घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों, खासकर उनके कम क्षमता उपयोग को ध्यान में रखा गया है और तदनुसार रक्षोपाय शुल्क की मात्रा का निर्धारण करने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया है। पहला उत्पादन लागत पर आधारित है जिसके लिए उचित समायोजन और संवर्धित मूल्य ह्रास की तुलना में केवल सामान्य मूल्य ह्रास प्रदान करने के बाद वर्ष 2000-01 (लेखापरीक्षित लेखा) और 2001-02 (अलेखापरीक्षित) की अवधि के लिए ईसीएच की विधिवत सत्यापित उत्पादन लागत और वास्तविक लागत को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के कारण अधिकतम क्षमता (गोपनीय) पर विनिर्माण की संभावित लागत को ध्यान में रखा गया है। घरेलू उत्पादकों ने लगाई गई पूंजी इत्यादि पर संभावित आय के आधार पर लाभ की कुछ मात्रा का दावा किया है, जिसे अपेक्षाकृत अधिक माना गया है और इसलिए भारित औसत उत्पादन लागत के आधार पर लाभ की कम राशि (गोपनीय) को उचित समझा गया है और उसकी अनुमति दी गई है। इसी प्रकार वर्ष 2001-02 (जनवरी तक) के लिए सत्यापित भारित औसत आधार पर ईसीएच की सीआईएफ आयात कीमतों पर भी विचार किया गया है। सीआईएफ आयात कीमत में औसत आधार पर ऋण अवधियों और उत्तराई प्रभासों के लिए समायोजन

किए गए हैं । आयातित ईसीएचकी पहुंच कीमत निकालने में सीमा शुल्क की लागू दर में परिवर्तन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा गया है । दूसरा परिकलन घरेलू उद्योग के पुनर्गठन से प्राप्त लाभ की मात्रा पर आधारित है । इस प्रकार से अनुसंशित रक्षोपाय शुल्क की राशि को उक्त दोनों में से न्यूनतम राशि तक सीमित किया गया है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए उचित होगी और जिससे उसे आयात संबंधी प्रतिस्पर्धा के प्रति सामयोजन करना सुविधाजनक बन जाएगा ।

घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजनों को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ रक्षोपाय शुल्क के उत्तरोत्तर उदासीकरण की जरूरत पर विचार करते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि भारत में ईसीएच के आयातों पर निम्नानुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए मूल्यानुसार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए जो कि ईसीएच के संवर्धित आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति तथा आगे और गंभीर क्षति होने के खतरे से घरेलू उद्योग की संरक्षा करने के लिए न्यूनतम है ।

अवधि	अनुसंशित कुल संरक्षण का स्तर	मौजूदा शुल्क ( % )	रक्षोपाय शुल्क ( % ) (2-3)
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रथम वर्ष	25 + 22	25 %	22
द्वितीय वर्ष	25 + 15		15
तृतीय वर्ष	25 + 09		09

[ फा. सं. एस.जी./आईएनवी/1/2002 ]

आर. के. गुप्ता, महानिदेशक (रक्षोपाय)

## OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2002

**Sub: Safeguard Duty investigation against imports of Epichlorohydrin into India under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the SGD Rules) read with Section 8B of the Customs Tariff Act 1975} - final findings.**

**G.S.R. 471(E).**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

**A. PROCEDURE**

The Notice of initiation of safeguard duty investigation concerning imports of Epichlorohydrin into India was issued on 14.03.2002 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 21.03.2002. A copy of the Notice alongwith copy of Application and a questionnaire was sent to all known interested parties to make their views known by 26<sup>th</sup> April 2002 namely:-

**Domestic Producers**

- (i) Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL), Chennai

**Importers/User Industries**

- (i) Dr Beck &co( India ) Ltd, Pune
- (ii) Atul limited, Valsad, Gujarat
- (iii) Synthetics & Polymer Industries, Ahmedabad
- (iv) Parikh Resins Ltd (Resinova Chemie Ltd), Kanpur
- (v) Resins and Plastics Ltd, Raighad
- (vi) Petro Araldite Pvt. Ltd, Chennai
- (vii) Parikh Resins and Polymers Ltd. Unnao, U.P.
- (viii) Bharat General Textile Industries, Calcutta
- (ix) Bengal Poly Resins Pvt Ltd, Calcutta
- (x) Delta Industrial Resin Pvt. Ltd, Mumbai
- (xi) Pragati Chemicals Ltd, Mumbai



- (xii) Kemwell Pvt., Ltd, Bangalore
- (xiii) IPCA Laboratories Limited , Mumbai
- (xiv) Easy Term Enterprise, Mumbai
- (xv) Ratanchand & Co. Mumbai
- (xvi) C.J.Shah & Company, Mumbai
- (xvii) Manali Chemicals, Mumbai
- (xviii) Urmi Chemicals, Mumbai
- (xix) Rasiklal & Co., Mumbai
- (xx) Alfa Chemical Corporation , Mumbai
- (xxi) Paresh Chemical Corporation , Mumbai
- (xxii) Rashmi Trading Company, Mumbai
- (xxiii) Beekay Enterprises; Baroda/ Mumbai

### **Exporters**

- (i) Daiso Co. Ltd., Japan
- (ii) Dow Chemical Company,U.S.A.
- (iii) Solvay SA, Belgium
- (iv) Hanwha Chemical Corp., Korea

### **Associations**

- (i) Chemical Industries Association, Chennai
- (ii) Indian Resin Manufacturers Association , Mumbai

2. A copy of the notice of initiation alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Belgium, China , Germany, Japan, Korea RP, U.K., USA and to the European Union, Delegation of the European Commission in India, New Delhi.

3. Request for extension of time to submit their reply was made by Dow Chemical Company,U.S.A.and Solvay SA, Belgium. The extension of time, prayed for, was acceded to and the parties concerned were informed accordingly.

4. Replies to the Notice dated 14.03.2002 and to the questionnaire were received from the following parties:-

### **Domestic Producers**

Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL), Chennai

**Importer/User Industries**

- (i) Atul Limited, Valsad, Gujarat\*
- (ii) Synthetics & Polymer Industries, Ahmedabad\*
- (iii) Parikh Resins Ltd (Resinova Chemie Ltd), Kanpur
- (iv) Bharat General Textile Industries, Calcutta\*
- (v) Petro Araldite Pvt. Ltd, Chennai\*
- (vi) Bengal Poly Resins Pvt. Ltd, Calcutta\*
- (vii) Delta Industrial Resin Pvt. Ltd, Mumbai\*
- (viii) Pragati Chemicals Ltd, Mumbai\*
- (ix) Kemwell Pvt., Ltd, Bangalore
- (x) Beekay Enterprises, Baroda

\* Through Counsel

**Exporters**

- (i) Daiso Co. Ltd., Japan
- (ii) Dow Chemical Company, U.S.A.
- (iii) Solvay SA, Belgium
- (iv) Hanwha Chemical Corp., Korea

**Associations**

Chemical Industries Association, Chennai

5. Verification of the information considered necessary for the investigation was done and to this end a team of officers visited the premises of domestic producer. The outcome of the investigations was conveyed to the domestic producer and a copy of the verification report was also placed in Public File.

6. A Public Hearing was given to all interested parties on 31st May 2002, notice for which was sent on 26.04.2002. During the Public Hearing the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 06.06.2002 collect replies filed by others on 07.06.2002 and to file rebuttals, if any, by 14.06.2002. The following parties attended the Public Hearing:

- (i) Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL), Chennai
- (ii) Atul Limited, Valsad, Gujarat
- (iii) Synthetics & Polymer Industries, Ahmedabad
- (iv) Parikh Resins Ltd (Resinova Chemie Ltd), Kanpur
- (v) Petro Araldite Pvt. Ltd, Chennai
- (vi) Delta Industrial Resin Pvt. Ltd, Mumbai
- (vii) Solvay SA, Belgium

- (viii) Hanwha Chemical Corp., Korea
- (ix) Delegation of European Commission (European Union),  
New Delhi

Some of the interested parties requested for another Public hearing on the ground that TPL has not effectively replied to their queries during the Public Hearing held on 31.05.2002, which has prevented them from effectively dealing with various issues. In this regard, it is observed that under the procedure followed, it is not mandatory for the domestic producers to provide on the spot clarification to the queries raised by other parties. The purpose of providing the opportunity of seeking clarification at the time of public hearing is to remove doubts in understanding of the submissions made by other parties. TPL had mentioned and it was agreed that they would provide additional information sought by other parties at the time of filing written submissions. Accordingly, TPL has provided the necessary clarification in their submissions. Further, only that information is taken into consideration, which is reduced in writing. All the information so received was placed in public file, besides handing over copies to the interested parties, who could rebut the same at the time of filing their rebuttals, if any. Some of the main points that were sought to be clarified by the interested parties related to capacity of TPL, increased imports, unforeseen developments, accelerated depreciation policy of TPL, feasibility of adjustment plans etc.. All these issues have been appropriately dealt with in the findings and I find no justification for any further public hearing in the matter.

Another request has also been made on 20 June, 2002 for providing a copy of the rejoinder (rebuttals) filed by the petitioners and for permission to file comments on the same. This request does not merit consideration, both on ground that it is made after completion of all procedure on 14.6.2002 and as per the procedure parties are at liberty to file rebuttals after collection of written submissions. The procedure does not envisage further submissions after filing of rebuttals. If such a request is allowed, it will be an unending process, leading to no finality at any stage. The request, therefore, could not be acceded to.

### **Domestic Industry**

The application for imposition of safeguard duty on ECH has been filed by Tamilnadu Petroproducts Ltd (hereinafter referred to as TPL for the sake of brevity). In India, ECH is produced by only TPL and they account for the entire domestic production. The application is, therefore, considered to have been made by the domestic industry producing ECH.

### **Product under Investigation**

The product under investigation is Epichlorohydrin (ECH). ECH is a basic organic chemical with chemical formula  $\text{CH}_2\text{-CH-CH}_2\text{Cl}$ , classified under

sub-heading No.2910.30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 and under 29103000 of the Indian Trade Classification (ITC) based on the Harmonised Commodity Description. This classification of Epichlorohydrin under the Customs Tariff Act, 1975 and the ITC has been indicated for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage of the product under investigation. ECH is produced by Chlorine addition to Propylene, which is akin to international standard of manufacturing. ECH is produced by obtaining Allyl Chloride by direct Chlorination of Propylene and Chlorine in gaseous phase at elevated temperatures. Chlorohydration of Allyl Chloride is carried out in aqueous medium using Chlorine to obtain Dichlorohydrin. Further Hydrolysis of Dichlorohydrin is carried out at boiling temperature of water using lime as saponifying agent. Hydrolysing reaction is accomplished in a stripping tower where ECH is stripped. The raw ECH is rectified in fractionation system. ECH is a Petrochemical used as key raw material in the manufacture of Epoxy Resins, Pesticides and certain Pharmaceutical formulations. Both, the imported ECH and the domestically produced ECH are alike.

### **Commitments undertaken and the applicable rate of duty**

ECH falling under Tariff heading No.2910.30 has been bound at 40% ad-valorem, with no quantity restrictions imposed on the imports. The applicable rate of import duty (basic + surcharge, if any) on ECH was 65% ad-valorem in 1994-95, which was gradually brought down to 42% in 1995-96, 32% in 1996-97, 25% in 1997-98 and 1998-99, increased to 27.5% in 1999-2000 and 2000-01, before restoring to 25% ad-valorem in 2001-02.

### **Increased imports**

ECH is imported into India mainly from Belgium, Germany, Japan, Korea (RP) and USA. The import and domestic production of ECH during last five years were as under:

**Table 1**

Year	Domestic Production (MT)	Imports(MT) Qty MT	Value (Rs.Lakhs)	Imports as a %age of Domestic Production
1996-97	3595	761	411.55	21.17
1997-98	2349	1931	901.41	82.20
1998-99	951	2933	1497.80	308.41
1999-00	951	4614	2104.74	485.17
2000-01	3620	4294	2550.28	118.61
2001-02(Jan)	2997	4971*	2171.91	165.87

\* As verified from the Customs authorities.

The import of ECH during the period between 1996-97 has increased in absolute terms from 761 MT in 1996-97 to 4294 MT in 2000-01. During the year 2001-02, for which the data has been verified with the Commissioners of Customs at the ports of imports upto January 2002, the import of ECH was 4971 MT. On pro-rata basis the import of ECH during the current year 2001-02 works out to 5965 MT.

On a comparison of end point to end point it is observed that the import of ECH has increased to more than 6 times from 761 MT in 1996-97 to 4971 MT in 2001-02 (upto January). It is important to note that the import of ECH peaked to 4614 MT in 1999-2000, before declining to 4294 MT in 2000-01 and again rising to 4971 MT in 2001-02 (upto January). The year wise increase in the import was 154% in 1997-98 over 1996-97; 52% in 1998-99 over 1997-98; 57% in 1999-2000 over 1998-99, a decline of 7% in 2000-01 as compared to 1999-00 and again an increase of 40% in 2001-02 (on pro-rata basis) over 2000-01. In absolute terms, therefore, the imports of ECH have increased over the years, except in the year 2000-01 when the imports declined by 7% as compared to the immediately preceding year. However, on an average, during the last three years i.e. 1999-2002 the imports of ECH on an average was 4958 MT per annum, which is 164% higher than the average imports of 1875 MT during the preceding three years i.e. 1996-99.

As regards increase in imports of ECH compared to domestic production, it is observed that the domestic production of ECH in 1996-97 was 3595 MT, which increased marginally to 3620 MT in 2000-01 and to 2997 MT in 2001-02 (upto January) i.e. to 3596 MT in 2001-02 (for the whole year) on a pro-rata basis.

The imports of ECH as a percentage of domestic production were 21.17% in 1996-97 which increased rapidly to 485.17% in 1999-2000 and thereafter declined to 118.61% in 2000-01 but increased again by about 47 percentage points to 165.87% in 2001-02. As compared to the initial figures of 21.17% in 1996-97, the imports show a substantially higher percentage – 165.87% of domestic production in 2001-02 which is almost eight times that of 1996-97. Even as compared to 1997-98, when the imports were 82.2% of domestic production, the imports percentage in 2001-02 has doubled as compared to the domestic production. The imports have thus increased both in absolute terms as well as relative to domestic production.

It has been submitted by some of the interested parties that 'safeguard measures' being 'emergency measures', the imports must show a sudden increase in a short span. To this end, they suggest that imports of ECH should be considered only during the last three years i.e. 1999-2000 to 2001-02. During this period, the imports of ECH have stagnated, being 4614 MT in 1999-2000, 4294 MT in 2000-01 and 3846 MT in 2001-02 (upto January) and therefore there is no 'increased imports' of ECH. I, however, find no support to this submission, either on the basis of facts or from the law. On facts, the imports in the current year i.e. 2001-02 (up to January) have increased by 40% over 2000-01. As regards the legal provisions, neither the domestic safeguard law nor the Agreement on Safeguards support this contention. In practice also most of the Members of WTO

have been analysing imports over a period of five years or more. Looking to the peculiar facts of this case, as discussed below, I hold that consideration of imports, as well as other parameters for the period 1996-97 onwards to be fully justified in this case.

### **Unforeseen Developments.**

The domestic producers have submitted that the production of ECH was conceived in the year 1992 as an import substitute to epoxy manufacturers, who had an installed capacity of about 9000 MT pa and the rate of duty on the import of ECH was 115% and that on epoxy resins 65% for general use and 20% for use in electronic industry. By the time the ECH plant came into production, the customs duties came down substantially and went on declining further. Some of their buyers could not bear the onslaught of increased imports of epoxy resins and finally closed down in the year 1998-99. Besides, the exporters reduced the prices of both ECH and epoxy resins and thereby captured the market, forcing the domestic producers to cut-down their production as they could not sell their products even at a price much below their variable cost.

It has been argued by some of the interested parties that there is no unforeseen development in the market place which could justify imposition of safeguard duty. According to them unforeseen developments shall normally include such of those developments which were not foreseen by the negotiators of a Member-country at the time of extending the concession or undertaking the said obligation under the aegis of WTO.

As regards the 'unforeseen developments' it is observed that the Appellate Body in US-Lamb (WT/DS177/AB/R, WT/DS178 AB/R, adopted 16<sup>th</sup> May 2001) stated that "unforeseen developments" is a circumstance whose existence must be demonstrated as a matter of fact for a safeguard measure to be applied consistently with Article XIX.

In this context, it is observed that it is a matter of fact that the import duty has been brought down sharply on ECH, between the period the production of ECH was conceived and the production actually was made available, which has coincided with sharp reduction in import prices of ECH during the period 1996-97 to 1999-2000. The CIF imports prices during the period declined from US \$ 1528 per Mt to US \$ 1059 per MT. However, the most pertinent fact in this regard is the lack of an internationally competitive manufacturing support. The domestic producers conceived the production of ECH on the basis that Propylene, the most important raw material for ECH production will be available to them from the Chennai Petroleum Corporation Ltd. (CPCL) but this did not come through, as their (CPCL) supplies were enough only for their existing customers. The alternative domestic source of Propylene supply was Indian Oil Corporation, Mathura, which is far away and involves high transportation cost besides being hazardous. IOC has also suspended the credit facility due to demand/supply gap. Efficient production of ECH thus depended on imported Propylene. Here again, the Chennai Port Trust does not allow imports of Propylene through Chennai Port

being hazardous. The domestic producers, therefore, created a small terminal facility at Cuddalore, 200 Kms from South of Chennai for facilitating imports through barges, which is quite cumbersome and costly. Besides the poor infrastructural facilities, high cost of power and financing make the domestic production of ECH further in-competitive compared to imported ECH. These unforeseen developments have resulted in increased imports of ECH coupled with the fact of reduction in import duty and imports being allowed without any quantitative restrictions.

### **Serious Injury**

The determination of serious injury requires evaluation of all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment.

While the rate and amount of the increase in imports of ECH in absolute terms as well as in relative terms has already been analysed under the heading 'increased imports', other aspects are discussed below:

#### **(a) Domestic Production**

An analysis of various factors attributing to the present status of domestic industry reveals that the only domestic producer of ECH namely M/s. Tamilnadu Petroproducts Ltd., commissioned their production in the last week of March 1995, producing only 5MT in 1994-95. During the period under consideration, TPL produced 3595 MT of ECH in 1996-97, 2349 MT in 1997-98, 951 Mt in 1998-99 and in 1999-2000 and 3620 MT in 2000-01. They produced 2997 MT of ECH in 2001-02 (upto January, 2002) which on pro-rata basis works out to 3596 MT for the whole of 2001-02. The domestic production thus declined from a peak of 3595 MT in 1996-97 to a bare 951 MT in 1998-99 and 1999-2000. Thereafter the domestic production of ECH went upto 3620 MT in 2000-01 and to 3596 MT (on pro-rata basis) in 2001-02.

Some of the parties have argued that the domestic producers had made an application for safeguard investigation against increased imports of ECH in 1998-99, when all the essential parameters for imposition of safeguard duty were manifold more in favour of the petitioner at that point of time, which was rejected by the Director General. If the petitioners did not have any case for imposition of safeguard duty on ECH then, they have no case now.

In this regard, it is observed that TPL had filed an application for imposition of safeguard duty on imported ECH in the year 1998-99 on 12.06.1998. It is a matter of fact. The more important fact, however, is, as mentioned above, that TPL commenced their production of ECH in the last week of March, 1995. Thus,

when TPL made the application on 12.06.98, they had a track record for the just three years immediately after commencing the production and the figures of production of ECH during the three years i.e. 1995-96, 1996-97 and 1997-98 were 3134 MT, 3595 MT and 2349 MT respectively and that of import as 2374 MT, 761 MT and 1931 MT respectively. An analysis of those figures did not support a prima facie case for initiation of a safeguard investigation against 'increased imports' of ECH causing serious injury to domestic producers of ECH and accordingly it was not considered appropriate to initiate a safeguard investigation at 'that' point of time.

As apprehended in 1998-99 by the domestic producers, however, the imports of ECH increased in the subsequent years. In 1998-99 the imports of ECH increased to 2933 MT from 1931 MT in 1997-98. The imports further increased to 4614 MT in 1999-2000; 4294 MT in 2000-01 and to 4971 MT (upto January) in 2001-02. The domestic production of ECH in 1998-99 and in 1999-2000 declined to a mere 951 MT. In 2000-01 and 2001-02 the domestic production increased to 3620 MT and 3596 MT (on pro-rata basis) respectively. This increase in domestic production in the last two years has, however, to be seen in the proper perspective. To meet with the competition from imports, in their application dated 12.06.98, TPL envisaged an alliance with Ciba Geigy for setting up a Joint Venture Company for manufacture of epoxy resins, thereby providing a venue for supply of ECH manufactured by them to this new company. Accordingly, a new company in the name of Petro Araldite Pvt. Ltd. was set up, which was commissioned in 1999. PAPL are into epoxy resins business and are one of the largest consumers of ECH in the country, sourcing their requirement of ECH exclusively from TPL, which explains the increase in domestic production of ECH by TPL in the years 2000-01 and 2001-02. But for this development, TPL would have not been able to find a reason to achieve higher productions. It is also pertinent to observe that the apparent domestic consumption from 1996-97 to 2001-02 (upto January, 2002) increased from 2546 MT to 6797 MT i.e. by 206% but the domestic production of ECH has remained almost stagnant at around 3600 MT per annum, which was the level of production in 1996-97 itself.

(b) **Capacity Utilisation**

TPL have stated their installed capacity of ECH as 10,000 MT per annum. Accordingly, they achieved capacity utilisation of 35.95% in 1996-97, which kept on falling to 23.49% in 1997-98, 9.51% in 1998-99 and also in 1999-2000. Keeping in line with the increased production in 2000-01 and 2001-02, as discussed above, the capacity utilisation also has shown improvement over 1998-2000 to 36.2% and 35.96% (on pro-rata basis) for the years 2000-01 and 2001-02 respectively. The capacity utilisation, however, remained at a low of about 36% at best during the period considered.

(b) **Sales**

TPL has considered sales of ECH to PAPL as captive consumption, but in view of the fact that PAPL is a separate joint venture entity, which is engaged in



the business of production of epoxy resins both for the domestic market, as well as for exports, it is not appropriate to consider sales of ECH by TPL to PAPL as captive consumption. In any case, whether used captively or sold in the market, it does not make any difference for the purpose of safeguard investigations. However, ECH used by PAPL in the export production of epoxy resins was sold by TPL on deemed exports basis under DEEC scheme. These sales of ECH are not being considered as a part of domestic sales.

TPL sold a total of 3753 MT of ECH in 1996-97, out of which 1785 MT were sold in the domestic market and balance 1968 MT were exported. In 1997-98, both the domestic sales and exports declined to 1389 MT and 19 MT respectively. In 1998-99 the domestic sales further declined to 1241 MT and exports were marginally improved to 118 MT. In 1999-2000, the domestic sales, including export sales in the domestic market on deemed export basis to PAPL were 1656 MT, out of which the sale to PAPL were 1196 MT for domestic consumption, 360 MT for use in export production on deemed export basis and 100 MT were sold to other buyers. In 2000-01, the total sales by TPL were 3221 MT, which included exports of 401.57 MT of ECH, 626 MT sales in the domestic market to buyers other than PAPL and the balance to PAPL including 1080 MT for export production on deemed export basis. In 2001-02, the total sales of ECH were 3326 MT, including 516 MT to domestic buyers other than PAPL and balance 2810 MT to PAPL including 1500 MT on deemed exports basis.

The table below gives details of Production, sales and closing stock of domestically produced ECH

**Table 2**

Year	Production (MT)	Sales of ECH (MT)					Closing Stock (MT)
		PAPL	Other buyers	Total Domestic sales	Exports including deemed exports	Total	
1996-97	3595	--	1785	1785	1968	3753	278
1997-98	2349	--	1389	1389	19	1408	1219
1998-99	951	--	1241	1241	118	1359	811
1999-00	951	1196	100	1296	360	1656	106
2000-01	3620	1113	626	1739	1482	3221	505
2001-02 (upto January)	2997	1310	516	1826	1500	3326	176

It is observed from the data tabulated above that the domestic producers sold a total of 1785 MT of ECH in the domestic market in 1996-97, which gradually declined to 1389 MT in 1997-98 and to 1241 MT in 1998-99. Their domestic sales improved subsequently only after PAPL commenced their production and started lifting ECH from TPL. The sales to PAPL resulted in total

212191/02-5

domestic sales improving to 1296 MT in 1999-00, 1739 MT in 2000-01 and to 1826 MT in 2001-02 (upto January). It is observed that the apparent domestic consumption (ADC) increased by about 167% from 1996-97 to 2001-02 (on pro-rata basis). Year wise the ADC increased over the previous year by about 30% in 1997-98; 26% in 1998-99; 42% in 1999-2000; 2% in 2000-01 and 13% in 2001-02. The domestic sales should have also increased accordingly, which is not the case. The domestic sales (excluding quantity supplied on deemed export basis) was 1826 MT till January in 2001-02 i.e. only 22% higher than 1996-97 on a pro-rata basis.

(d) **Stocks**

The closing stocks of ECH of the domestic producers was 278 MT in 1996-97, 1219 MT in 1997-98, 811 MT in 1998-99, 106 MT in 1999-00, 505 MT in 2000-01 and 176 MT at the end of January 2002. The closing stock gradually reduced from a high of 1219 MT in 1997-98 to 106 MT in 1999-00 before rising to 505 MT in 2000-01 and then again declining to 176 MT at the end of January 2002.

(e) **Employment**

The domestic producers have submitted that at no point of time the plant could be operated at more than 36% plant capacity, which has led to a sense of insecurity and loss of employment of around 270 personnel – 160 officers and about 110 from the staff cadre, over the last five years.

(f) **Productivity**

The productivity of TPL for ECH in MT per employee was 29.95 MT in 1996-97. It declined to 19.58 MT in 1997-98 and to a mere 7.93 MT during 1998-99 and 1999-2000. However with the increase in production, the productivity has increased to 30.16 MT in 2000-01 and to 32.21 MT in 2001-02. As regards productivity per unit capital employed, it declined from 28.54MT/crore of Rs. in 1996-97 to 17.88 in 1997-98, 6.89 in 1998-99 and to 6.57 in 1999-2000. It increased to 24.84 MT/crore of Rs. in 2000-01 but again declined to 19.92 MT/crore of Rs. in 2001-02.

(g) • **Profitability**

TPL have been selling ECH at a loss. Their sale realisation is below the cost of production and hence they are incurring losses. Over the years their cost of production of ECH was as under:

**Table 3**

<b>Year</b>	<b>Cost of Production (Rs. MT)</b>	<b>Sales realisation (Rs.MT)</b>
1996-97	1,33,114	58426
1997-98	1,21,734	65531
1998-99	2,71,020	67341
1999-2000	3,36,615	66769
2000-01	1,39,906	75363
2001-02	1,11,673	65107

TPL has incurred losses on their ECH production. The year wise losses were Rs. 26.02 crores in 1996-97, Rs. 18.52 crores in 1997-98, Rs.16.85 crores in 1998-99, Rs.21.02 crores in 1999-00, Rs.26.08 crores in 2000-01 and Rs.27.25 crores (un-audited) in 2001-02. The losses which initially declined in 1997-98 and 1998-99 as compared to previous year have started increasing from the year 1999-2000 onwards and reached to a peak of Rs. 27.25 crores in the current year. Even with higher production and higher sales in 2000-01 and 2001-02, TPL have incurred higher losses in these years.

From the above analysis, it is observed that TPL suffered serious injury as reflected by a significant overall impairment in their performance in the years 1998-99 and 1999-2000, when their production dipped to a low of 951 MT consecutively for two years with domestic sales touching to the lowest of 1241 MT in 1998-99 and remaining at 1296 MT in the next year. Their capacity utilisation also dropped to a bare 9.51% during this period and they incurred heavy losses of about Rs. 38 crores during these years on their ECH operations. Apprehending the onslaught of imports, TPL had sought safeguard protection in the year 1998-99 and had worked out an adjustment plan for itself involving various measures, including setting up of PAPL. These steps did improve their performance in the subsequent years i.e. 2000-01 and 2001-02 but as no safeguard protection was given to them, the imports of ECH continued unabated with 4294 MT landing into India in 2000-01 and 4971 MT upto January 2002. With the setting up of PAPL, TPL were able to increase their production, capacity utilisation, productivity and domestic sales as compared to the previous year but the continued threat of serious injury loomed large on them in the shape of loss in productivity in terms of capital employed, stagnant domestic production, capacity utilisation and sales not keeping pace with the increase in apparent domestic consumption with increased losses of Rs.26.08 crores incurred in 2000-01 and Rs.27.25 crores (un-audited) in 2001-02, i.e. a total loss of Rs. 53.38 crores in 2000-01 and 2001-02 as compared to Rs. 37.87 crores in 1998-99 and 1999-2000.

**Cause of Injury**

The table below shows domestic sales (excluding domestic sales for export production on deemed export basis) of ECH by TPL, imports of ECH and the shares of domestic production and imports in Apparent Domestic Consumption (domestic sales + imports):

**Table 4**

<b>Year</b>	<b>Domestic sales (MT)</b>	<b>Imports (MT)</b>	<b>ADC (MT)</b>	<b>Share of domestic sales in ADC %</b>	<b>Share of imports in ADC%</b>
1996-97	1785	761	2546	70.1	29.9
1997-98	1389	1931	3320	41.8	58.2
1998-99	1241	2933	4174	29.7	70.3
1999-00	1296	4614	5910	21.9	78.1
2000-01	1739	4294	6033	28.8	71.2
2001-02 (upto January)	1826	4971	6797	26.86	73.14

From the data tabulated above, it is observed that TPL had a market share of 70.1% in the Apparent Domestic Consumption (ADC) in 1996-97, which declined to 41.8%, 29.7% and to 21.9% in 1997-98, 1998-99 and 1999-2000 respectively. The share lost by the domestic producers was captured by the imports, which increased from 29.9% in 1996-97 to 58.2% in 1997-98, 70.3% in 1998-99 and to a high of 78.1% in 1999-2000. With the setting up of the Joint Venture Company PAPL, the share of domestic producers of ECH improved marginally to 28.8% in 2000-01 before declining to 26.86% in 2001-02, with the share of imported ECH falling marginally to 71.2% and again rising to 73.14% respectively during this period.

It is observed that the injury to the domestic producers of ECH has more prominently manifested itself in the form of losses incurred by them, particularly so during the most recent period i.e. 2000-01 and 2001-02. In this regard it is observed that ECH was imported into India during the period 1996-97 to 2001-02 (upto January) at prices as mentioned below in the table:

**Table 5**

Year	CIF Import Prices in US\$/MT	CIF Import Prices in Rs./MT	Landed price (CIF +Import duty)
1996-97	1528	54077	71382
1997-98	1235	46681	58352
1998-99	1242	51075	63844
1999-00	1059	45621	58167
2000-01	1318	59483	75841
2001-02 (upto January)	1090	43691*	54057*

\*Based on Customs Data

TPL has stated that they sell ECH in the domestic market keeping in view the landed price parity and that due to steady decline in import price, they were forced to reduce their selling prices resulting into financial losses to them. It is a matter of fact that TPL have been selling ECH at prices much below their cost, resulting in financial losses to them. ECH is importable into India without any quantitative restrictions. As such, the landed price of imported ECH governs the domestic market price since it provides the comparative bench mark for the buyers to make their buying decisions.

It is also a matter of fact that the CIF import price of ECH have steadily declined. In 1996-97, the CIF import prices in US\$/MT were on an average 1528, which thereafter declined to 1235, 1242 and 1059 in 1999-2000 before rising to 1318 US\$/MT in 2000-01 and again declining to US\$ 1090 per MT in 2001-02 (upto January). The increase in imports coincides with this decline in price. In 1996-97, the imports were 761 MT, which increased to 1931 MT, 2933 MT and peaked to 4614 MT in 1999-2000 with the lowest average CIF price of 1059 US\$/MT. By the year 1998-99 and 1999-2000, the domestic production was reduced to a bare 951 MT per annum. Having almost wiped out the domestic production, the import prices increased to 1318 US\$/MT but as the domestic production was raised to 3620 MT in 2000-01, which was mainly on account of setting up of PAPL and their buying support extended to TPL, the import prices again have come down to almost their lowest level at 1090 US\$/MT in 2001-02, threatening the domestic production of ECH.

It has been argued by some of the interested parties that CIF price of imported ECH in US\$ is of no relevance to TPL as their consumers have paid for the material in Indian rupees and, therefore, import price in Indian rupees alone is of relevance both to the consumers and TPL. In Indian rupees, the import price has increased by about 20% in 2001-02 as compared to Rs.45621 PMT in 1999-2000. TPL were neither selling reasonable volume in the past nor intended to sell

even when the prices were very substantially higher, for instance in 2000. Such being the case, they submitted that decline in prices is not relevant to TPL.

I am afraid this argument is wholly untenable. The petitioners have set-up a plant with a capacity of 10,000 MT per annum for the manufacture of ECH at a huge investment. They have not set up this plant for idling. In fact no manufacturer can be expected to set-up the plant without any serious intention of supplying the material to its customers. The fact of the matter is that PAPL started buying material from TPL somewhere in 1999. Prior to that TPL was supplying ECH only to other domestic buyers but their sales to them kept on declining year after year i.e. from 1785 MT in 1996-97 to 1389 MT in 1997-98, 1241 MT in 1998-99 and to a mere 100 MT in 1999-2000, coinciding with the decline in landed prices of imported ECH, which came down from Rs.71382/MT in 1996-97 to Rs.58167 per MT in 1999-2000. Both at the end of 1997-98 and 1998-99, they carried inventory of 1219 MT and 811 MT respectively. In the wake of these facts, it cannot reasonably be argued that TPL did not want to supply material to its buyers. They had all the reasons to explore all possibilities to sell off their material to buyers.

Some of the parties have stated that the quality of ECH manufactured by TPL was not upto the mark and that the imported ECH was of a better quality for manufacture of epoxy resins of different grades. In this regard it is observed that TPL is an ISO 9002 accredited company. They have claimed that their product conforms to international standards set for ECH. A copy of characteristics of ECH manufactured by TPL and the imported ECH was also produced by the applicants which revealed that their product is fully compatible with the imported ECH with regard to various quality parameters. TPL are in the business of ECH for the last six years and ECH manufactured by them undergoes stringent quality checks before it is sent to the customers. Samples are tested at every stage of production starting from raw materials to the finished product. They have been supplying ECH to PAPL who manufactures epoxy resins for export purposes and to the pharmaceutical industry who are extremely quality conscious. In view of this it is considered that the quality of ECH provided by TPL was not the cause for increased imports.

One factor that has been pointed out by some of the interested parties is the assertion of the Directors of TPL in their Balance Sheets that they restricted supplies of ECH to remunerative markets. I see nothing in this assertion that will support the claim that TPL refused supplies of ECH to their buyers. Obviously TPL could not have been expected to keep on producing ECH and sell it at heavy losses, when they were already carrying on inventories and were not able to sell even the small quality of ECH that they produced.

As observed above, the reason for the domestic buyers to source their requirements of ECH through imports appeared to be the cheaper prices of imports. In this context it is also important to observe that in the year 2001-02, the imports of ECH have increased from 1102 MT in the First Quarter at an average CIF price of Rs.53935/MT to 1232 MT in the Second Quarter at an average CIF price of Rs.45098/- MT and to 1905.6MT in the Third Quarter at an average CIF

price of Rs.38954/ MT. In January 2002, 731.5 MT of ECH was imported at an average CIF price of Rs. 38219/MT. It is thus observed that the quantum of ECH imports has been increasing with the declining prices.

It has been argued by some of the parties that landed price of ECH imported in India showed an upward trend in 2000-01, providing a better opportunity to TPL to recover their costs. In this regard, I observe that the factors that influenced the prices of imported ECH must have also impacted upon the domestic production of ECH and, therefore, an increased CIF price of imported ECH does not necessarily mean that it provided an opportunity to TPL to improve their sales. As a matter of fact, all along TPL's cost of production has been much higher than the landed price of imported ECH and they had been trying to sell ECH in domestic market keeping the landed price parity in view. An important aspect tilting the decision to procure ECH in favour of the imported material, however, has been the long credit periods between 90-120 days associated with the imports. As a sequel TPL also was forced to extend such facility to their buyers affecting their liquidity position. The problem was compounded by suspension of credit terms by IOC, Mathura on Propylene supplies. Another aspect worth noting is that in a falling market regime the domestic buyers expect prices to be fixed based on expected landed price parity to prevent any further bookings. Besides, spot prices most often tend to be significantly lower than contractual prices, which has a direct bearing on domestic prices.

It has been argued by some parties that if the cause of injury to domestic producers was cheaper imports it does not hold good any longer as the import prices of ECH are likely to go up due to increase in the prices of raw materials Propylene and Chlorine and it has been suggested that decision to impose safeguard duty may be taken on the basis of prevailing international prices. In this regard it is observed that the current CIF prices of ECH cannot be the basis for arriving at a decision since post investigation price have no bearing on the prices prevailing during the period under consideration. The import prices may have increased due to various factors which would also influence the domestic cost of production. It is neither practicable nor desirable to base the findings on post investigation prices.

It has also been claimed that the reason for the woes of TPL is loss of its export market that has declined and that TPL made no serious efforts to improve their export performance and not the imports of ECH into the country. It has been further stated that since TPL has been exporting in the past rather than supplying the same to the Indian consumers the production of ECH to such an extent is not available to the domestic consumers. In this regard, it is observed that TPL has specifically mentioned in their application that in spite of the constraints they were forced to export ECH at low realisation to improve their capacity utilisation and to bring down cost. It is important to keep in mind that the production line of ECH is common to both domestic consumption and export market. A domestic industry that was not able to compete in the domestic market could hardly be expected to compete internationally. The injury caused by imports had its effect also on the export performance of TPL. However, TPL did supply 1500 MT of ECH to PAPL

in 2001-02 on deemed export basis under DEEC scheme, which are considered as exports without the goods leaving the Indian shore.

In conclusion it is observed that the domestic producer of ECH have suffered serious injury and face further threat of serious injury caused by increased imports of ECH.

### **Positive Adjustment**

The domestic producer has submitted details of efforts being made by them for making a positive adjustment to meet with the situation of competition offered by the increased imports. The applicants have proposed to take the following measures to bring down their cost of production to improve their competitiveness over a period of 3 years namely :

- (a) Build an international sized terminal at Ennore Satellite port to handle a variety of Petroleum products / other chemicals which will solve their problem of high demurrage costs incurred by them for importing Propylene at Cuddalore and the high transportation cost for bringing the domestic Propylene over long distances. This they expect to be completed by the year 2004. The cost of demurrage and higher transportation cost which could be saved have been worked out by them to be approximately Rs 3000 - 5000 / MT on ECH.
- (b) With a view to ensuring steady availability of Chlorine which is one of the main raw materials for Epichlorohydrin manufacture they have acquired the Heavy Chemicals division of SPIC and further they have planned to set up captive power plant in the premises of the Heavy Chemicals Division with the sole intention of reducing Chlorine cost which in turn would help ECH unit achieve cost competitiveness. The Chlorine transfer price which is presently Rs 4500 /MT could be reduced to Rs 1500/ MT over the next 3 year period by way of installing the captive power plant.
- (c) Sourcing Lime which is one of the raw materials at lower cost and further interact with indigenous Lime producers for improving its purity to minimum of 90 % which would solve process related problems and reduce cost.
- (d) The accelerated depreciation policy of TPL would ensure that the depreciation cost is written off by 2004-05 which would enable them to be highly competitive compared to that of the other developed nations. It has been stated that the overall Cost of Production of Rs 111,673 / MT during 2001-02 , shall over the four year period ( in the year 2005-06) will get reduced to Rs 50,423 /MT.



- (e) Installation of new mixer for Allyl Chloride production in ECH plant for reduced consumption of raw materials and for increasing the on stream efficiency.

Some of the interested parties have expressed doubts about the feasibility of the adjustment plans and the likely quantum of savings in cost of production of ECH. With regard to the accelerated depreciation of TPL it has been stated that the maintenance cost in a chemical plant that too in a fully depreciated plant would be quite high and such costs would more than off set the reduction in the form of lower depreciation. Some of the interested parties have stated that the adjustment plans envisaged by TPL neither quantified the associated investments nor quantifies the likely benefit. The adjustment plan are mere statements, unsubstantiated and unaccompanied with necessary evidence. Some of the interested parties have claimed since TPL has commissioned the captive power plant and it is already operational, the cost of chlorine should have already come down and, therefore, this cannot form part of their future adjustment plan. Similarly with regard to Allyl mixer plant it has been argued that the same has already been installed and benefits must have started accruing and, therefore, this also needs to be ignored.

The adjustment plans furnished by the applicants have been examined. The cost reduction efforts on account of accelerated depreciation, though it may be in accordance with generally accepted accounting principles and the company may be entitled for such benefits but as the same cannot be recovered through product price, it needs to be excluded for the purpose of arriving at the cost of production and only normal rate of depreciation is being allowed in working out the quantum of safeguard duty.

To reduce the power cost, steps have already been taken by TPL towards setting up of captive power generation facility. The facility has already been installed and expected to be commissioned by June 2002 which would get stabilised over a period of next two years. This would also bring down considerably the maximum demand charges gradually over a period of time, that are being paid by TPL to the Tamil Nadu Electricity Board, and as a sequel chlorine cost could be reduced considerably. The Allyl Chloride Mixer has been commissioned in March 2002 after the notice of initiation for safeguard investigation was issued. Efforts are being made by TPL to stabilise the reactor for efficient consumption norms, which would depend to a considerable extent on the capacity utilisation. All this is an ongoing exercise, which would continue for increasing the efficiency and onstream factor to the optimum. As regards the terminal at Ennore, TPL has promoted a company Van Ommeren Mac Tank Terminals now known as Vopak Sical Terminal Limited with equity participation by Vopak (40%), Sical (5%), TPL (35%) and TIDCO (11%). TPL have proposed setting up of 32 tanks for handling a variety of petro-chemical products and have already acquired about 30 acres of land for the project. They have obtained necessary clearances from the Tamilnadu Pollution Control Board. The raw material and finished product traffic figures of the TPL project have been factored in the overall traffic figures of the first corporatised port in the country. The port

has already started commercial operation since June 2001 handling Coal for the thermal power plant set up by TNEB. SICAL a sister company of TPL is the sole handling agency for coal. Phase II of the port envisages setting up of 4 berths, 3 for liquid cargoes and one for coal. The port authorities have already obtained, in principle clearance from the Government of India for these projects. The port management have called for an expression of interest for a marine liquid terminal at Ennore. TPL have submitted their documents for the same which is expected to be finalised by end of September 2002. The Ennore port expects this to be operational by 2004. TIDCO has also proposed a petrochemical park adjacent to the port and have already acquired about 2500 acres of land and a number of prospective players are in talk with TIDCO. There is a possibility of a co-operative effort on this front between TPL & TIDCO. After due analysis of the restructuring plans and keeping in view the possibility of implementation of the plans, it is considered that the domestic producer would need protection for a period of three years to prevent occurrence of serious injury and to make positive adjustment to the competition offered by imports.

### **Public Interest**

Some of the parties have argued that imposition of safeguard duty would not serve any public interest. On the contrary imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end user industry may close down. In this regard, it is observed that the expression 'public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone. It is a much wider term, which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported ECH in the hands of buyers and, therefore, it may also effect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition of safeguard duty is to provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of safeguard duty, for the period and to the extent just adequate, would, therefore, not only minimise the adverse effect, if any, for the customers but also allow them a wider choice to source their requirements and at competitive prices. The domestic producers who have set up plants with huge public investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. 'Safeguard duty', which would enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports, will, therefore, also be in the long-term interest of the buyers of ECH as well as of the buyers of products manufactured therefrom. It is, therefore, considered that imposition of safeguard duty on ECH will be in public interest.

Some of the parties have argued that the applicant being the sole producer of ECH, imposition of safeguard duty would lead to a monopolistic situation and TPL would exploit the domestic market. It is appropriate to observe here that the domestic producer has a total capacity of 10,000 TPA as compared to substantially higher capacity of exporters. The imports of ECH are allowed into India without any quantity restrictions. In the light of unrestricted imports it is not

correct to presume that TPL enjoyed/enjoys any monopoly particularly when imports accounted for about 70%, on an average, of the apparent domestic consumption during the period 1998-99 to 2001-02 (upto January). The law also does not envisage that interest of a single producer should not be protected even if it rightly deserves to be protected. Imposition of safeguard duty is not aimed at encouraging monopolistic practices but at protecting the interests of domestic producers, if increased imports cause or threaten to cause serious injury to them so as to allow them time to make positive adjustment with the new situation of competition offered by the increased imports.

Some of the parties have argued that TPL is not capable of meeting with the domestic demand of ECH and hence any imposition of safeguard duty would benefit only PAPL, to whom TPL are committed to supply ECH. It has been claimed that the capacity created by TPL is never tested in terms of actual production on continuous basis and the maximum achieved production can only be considered as the capacity of TPL. In this regard, it is observed that the domestic producer has furnished documentary evidence of their capacity on a confidential basis. They have stated that production can be stepped up in a short span of time if the opportunity is afforded to them to run the plant at higher load factor and meet the demand. I do not agree that in the circumstances of this case, where domestic producers were not able to sell the material to buyers only the quantity produced should be considered the capacity of the plant. In the absence of any evidence made available to the contrary, no ground exists to hold that they do not have adequate capacity to meet the domestic demand or to hold that the imports were necessitated because TPL was not in a position to cater.

Further, it is observed that TPL has set up a plant with installed capacity of 10,000 MT per annum. As verified, TPL achieved the highest production of 547 MTs in a month and 28.14 MT in a single day. Accordingly, there is no doubt that they can produce 6500 – 8500 MT per annum of ECH. As against this the Apparent Domestic consumption of ECH during the last three years i.e. 1999-2000, 2000-01 & 2001-02 (upto January) has been of the order of 6000 to 8000 MT per annum, including the requirement of PAPL. In view of the above, I observe that it will not be fair to hold that TPL are not able to cater to the domestic requirements of ECH.

It may also be pertinent to mention here that consequent to Ciba India Pvt. Ltd. (CIPL) divesting their status in PAPL in favour of Vantico Performance Polymers Pvt. Ltd., TPL had to agree to waive the right of first refusal in respect of shares sought to be sold, cessation of existing supply agreement for supply of ECH to PAPL to be superseded by a new supply agreement and release CIPL from its obligation and duties subsisting under various agreements. In consideration of this premature termination of the contracts and for surrendering the above rights a sum of Rs.630,248 thousands was settled by CIPL as compensation to be paid to TPL. Besides PAPL has opposed imposition of safeguard duty on ECH as a consumer of ECH and being the largest manufacturer of epoxy resins although PAPL is jointly owned by TPL alongwith M/s. Vantico International. There is, therefore, no ground to presume that interest of TPL and PAPL coincide in seeking safeguard duty imposition on ECH.

It is, therefore, considered that imposition of safeguard duty on ECH will be in Public Interest.

### **Provisional Safeguard Duty**

Since on completion of the investigation final findings have been made, it is not considered necessary to recommend any provisional measures in the present case.

### **Share of Countries in Export to India**

As per verified information, the share of countries in export of ECH to India during 2001-02 (upto January) was as under :

Country/territory	Quantity (MT)	%age share
Belgium	618	12.43
Germany	1109	22.31
Japan	364	7.32
Korea RP	1515	30.48
USA	1365	27.46
<b>Total</b>	<b>4971</b>	<b>100</b>

### **CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

In view of the findings above, it is concluded that increased imports of ECH into India have caused and further threatened to cause serious injury to the domestic producers of ECH and it will be in the Public interest. to impose safeguard duty for a period of three years on imports of ECH into India.

In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent serious injury to the domestic industry and facilitate positive adjustment, the peculiar circumstances of the domestic industry, particularly their low capacity utilisation has been kept in mind and accordingly two alternatives have been considered for working out the quantum of safeguard duty. One based on the cost of production for which the duly verified cost of production for ECH for the period 2000-01 (audited accounts) and for 2001-02 (un-audited), after making suitable

adjustments and providing only normal depreciation as against accelerated depreciation and the probable cost of manufacture at optimum capacity (Confidential) being more reflective of the true cost has been taken into account. The domestic producers have claimed a certain amount of profit on the basis of expected return on capital employed etc. which is considered to be on the higher side and, therefore, a lower amount of profit (confidential) based on the weighted average cost of production has been considered appropriate and allowed. Similarly, the C.I.F. import prices of ECH also have been considered on verified weighted average basis for the year 2001-02 (upto January). Adjustments have been made in the C.I.F. import price for credit terms and landing charges on an average basis. Change in the applicable rate of customs duty, if any, has been taken into account in working out the landed price of imported ECH. The other calculation has been based on the extent of benefit flowing from the restructuring of domestic industry. The amount of safeguard duty so recommended has been restricted to the lower of the two being the minimum that would be adequate to remove injury to the domestic industry and to facilitate them to adjust to the import competition.

Considering the need to progressively liberalise the safeguard duty in order to facilitate positive adjustments by the domestic industry, it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of ECH into India at the rates specified below on ad-valorem basis for a period of three years as under being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury caused and further threatened to be caused by the increased imports of ECH.

Period	Level of Total Protection Recommended (%)	Existing Duty (%)	Safeguard Duty Recommended (%) (2-3)
(1)	(2)	(3)	(4)
First Year	25+22	25%	22
Second Year	25+15		15
Third Year	25+09		09

[F.No. SG/INV/1/2002]

R.K. GUPTA, Director General (Safeguards)

